सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 115, नई दिल्ली, मंगलवार, 21 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिर भेजा समन
05 दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी पंजीकरण होगा आसान
08 भारत में कोई भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं करता वोट

आज का सुविचार

जिस व्यक्ति का मन का भाव सच्चा होता है, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है।

इनसाइड

एचएसआरपी के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, बनारस में 5.50 लाख वाहन स्वामियों को नोटिस

वाराणसी। वाराणसी में 11. 87 लाख 549 दोपहिया, चार पहिया और तीन पहिया वाहन हैं। इनमें से 6.34 लाख 654 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हैं। 5.52 लाख 895 वाहन ऐसे हैं, जो कि सामान्य रजिस्ट्रेशन प्लेट ही फर्राटा भर रहे हैं।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की समयसीमा समाप्त होने के बाद परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। आरटीओ ने ऐसे वाराणसी जिले में 5.50 लाख वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा है। साथ ही कहा है कि अब चालान काटने और जुर्माना वसूलने का सिलसिला शुरू होगा। बिना एचएसआरपी वाले वाहन स्वामियों से 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाता है। प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रवर्तन की टीमें भी लगाई जा रही हैं।

वाराणसी में 11. 87 लाख 549 दोपहिया, चार पहिया और तीन पहिया वाहन हैं। इनमें से 6.34 लाख 654 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हैं। 5.52 लाख 895 वाहन ऐसे हैं, जो कि सामान्य रजिस्ट्रेशन प्लेट ही फर्राटा भर रहे हैं। करीब एक लाख व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 40 हजार वाहनों में प्लेट नहीं लगे हैं। इसका संज्ञान लेकर ही आरटीओ ने वाहन स्वामियों के पास मोबाइल पर मैसेज के जरिये नोटिस भेजा है। लिखा है कि आपके वाहन में एचएसआरपी नहीं लगा है। बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाए वाहनों को सड़क पर न दौड़ाएं। अन्यथा वाहन का नियमानुसार चालान होगा।

इसी लिहाज से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रवर्तन की टीमें लगाई जा रही हैं। एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में एचएसआरपी की अनिवार्यता के बाद वाहन स्वामियों को 15 फरवरी 2023 तक इसे लगवाने का मौका दिया गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ।

डीटीसी बसों में आग लगने के लिए कौन और क्यों है मुख्य रूप में जिम्मेदार ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की जनता जिन्हे सार्वजनिक सवारी सेवा की जरूरत है उसके लिए आज की तारिख में उपलब्ध मुख्य साधन है सिर्फ डीटीसी और कलस्टर बसे।

क्योंकि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों, जनहित की नीतियों और जनप्रिय आदेशों के कारण दिल्ली में एसटीए परमिट पर चलने वाले वाहन (आरटीवी, मेट्रो फीडर, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, ईको फ्रेंडली सेवा,) लगभग सड़को से हट कर वाहन मालिको के घर/पार्किंग/ सड़को पर खड़े हो गए हैं।

यह सब वो वाहन सेवा कहलाती रही हैं जिन पर बेखौफ दिल्ली की जनता दिन-रात अपना सफर तय करते रहे हैं, पर अब दिल्ली की जनता सिर्फ डीटीसी और कलस्टर बसों के भरोसे पर है ।

दिल्ली में हर दिन डीटीसी और कलस्टर बसों को खराब होकर सड़को पर जाम लगवाते आप सभी देखते रहते होंगे यह है दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की विश्व विख्यात सुरक्षित बस सेवा।

पिछले कुछ समय से डीटीसी की बसों में चलते हुए पुर्जे और बस बॉडी के टूटने की भी खबरे जोर में है पर सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक ख़बर है चलती डीटीसी बसों में आग लगना जिसके लिए दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने जांच कमेटी भी बनाई थी पर सब कुछ मिला कर असर जीरो और डीटीसी बसों में आग लगने का सिलसिला जारी है। दिल्ली परिवहन निगम जिन बसों को स्क्रैप करके कुछ पैसा इक्ट्ठा कर नई बसे खरीद सकती हैं वह भी स्वाहा यानि खत्म और इन सभी बातों का जिम्मेदार कौन और कहा, बड़ा सवाल ?

जनता की जान जोखिम में डालने वाला आख़िर कौन ?

टोलवा की जनता से अपील

डीटीसी की बसों में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी या नुकसान मिलने पर अन्य सभी के साथ परिवहन आयुक्त दिल्ली से हर्जाने की भरपाई की मांग करना शुरू करे।

टोलवा का दावा है की डीटीसी में चलने वाली बसों का नियम के अनुसार दिल्ली की सड़को पर चलने का समय समाप्त हो चुका है पर परिवहन आयुक्त द्वारा जनता को बसों की गिनती दिखाने के लिए इन बसों को नाम के लिए दिल्ली की सड़को पर चलने के लिए 10 साल की जगह 15 साल का समय कागजों में कर दिया पर वह यह याद नहीं रख पाए की कॉर्पोरेशन के अंतर्गत चलने वाले बसो को सड़को पर चलने के लिए सिर्फ आयु सीमा नहीं देखी जाती, समय सीमा बची होने पर भी नियम के अंतर्गत यह बसे सड़को पर चलने से खत्म हो जाती हैं और वह है नियम बसों की किलोमीटर से (अगर कोइ भी बस समय सीमा के रहते हुए किलो मीटर पूरे कर चुके तो या तो वह स्क्रैप होगी या उस बस का इंजन नया लगवाना आवश्यक है और परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देश ही सिर्फ दिल्ली में डीटीसी की बसों में होने दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है)।

दिल्ली की जनता से अपील परिवहन आयुक्त को डीटीसी बसों में होने वाले नुकसान के प्रति जिम्मेदार मानते हुए उनसे नुकसान की भरपाई की मांग अवश्य करें।

जनहित में जारी

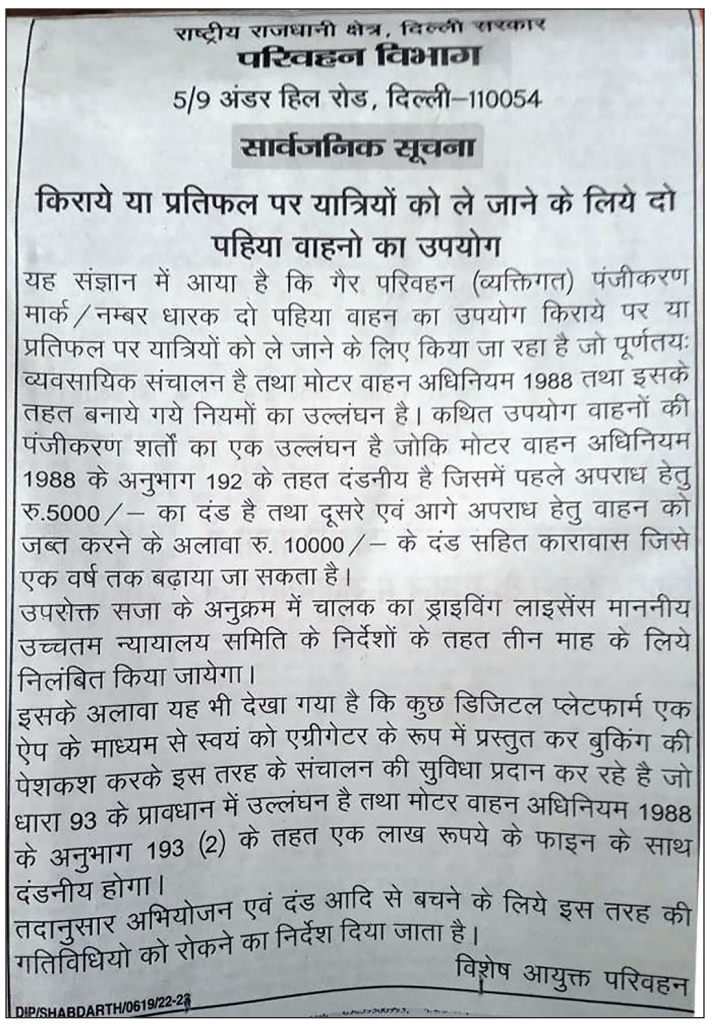

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054

सार्वजनिक सूचना

किराये या प्रतिफल पर यात्रियों को ले जाने के लिये दो पहिया वाहनो का उपयोग

यह संज्ञान में आया है कि गैर परिवहन (व्यक्तिगत) पंजीकरण मार्क/नम्बर धारक दो पहिया वाहन का उपयोग किराये पर या प्रतिफल पर यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा है जो पूर्णतयः व्यवसायिक संचालन है तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लंघन है। कथित उपयोग वाहनों की पंजीकरण शर्तों का एक उल्लंघन है जोकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 192 के तहत दंडनीय है जिसमें पहले अपराध हेतु रु.5000/– का दंड है तथा दूसरे एवं आगे अपराध हेतु वाहन को जब्त करने के अलावा रु. 10000/– के दंड सहित कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त सजा के अनुक्रम में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय समिति के निर्देशों के तहत तीन माह के लिये निलंबित किया जायेगा।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ डिजिटल प्लेटफार्म एक ऐप के माध्यम से स्वयं को एग्रीगेटर के रूप में प्रस्तुत कर बुकिंग की पेशकश करके इस तरह के संचालन की सुविधा प्रदान कर रहे है जो धारा 93 के प्रावधान में उल्लंघन है तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 193 (2) के तहत एक लाख रूपये के फाइन के साथ दंडनीय होगा।

तदानुसार अभियोजन एवं दंड आदि से बचने के लिये इस तरह की गतिविधियो को रोकने का निर्देश दिया जाता है।

विशेष आयुक्त परिवहन

DIP/SHABDARTH/0619/22-23

फिर डीटीसी की लो फ्लोर बस में लगी आग, इस महीने यह दूसरी घटना

एनटीवी संवाददाता

बादली क्रॉसिंग के पास रविवार दोपहर करीब 12 बजे रूट बस नंबर डीएल-1पी-सी 8774 से अचानक धुआं निकलने लगा।

नई दिल्ली। गर्मी के दस्तक देने से पहले ही एक बार फिर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की लो फ्लोर बस में आग लग गई। बादली क्रॉसिंग के पास रविवार दोपहर करीब 12 बजे रूट बस नंबर डीएल-1पी-सी 8774 से अचानक धुआं निकलने लगा।

प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल इसकी सूचना दी। तब तक बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की दो गाड़ियां पहुंच गई और आग को बुझाया। हालांकि इस घटना में कोई यात्री या कर्मी जख्मी नहीं हुआ है। इसी महीने डीटीसी की एक और लो फ्लोर नॉन एसी बस में कंझावला के नजदीक आग लगने से बस जल गई थी।

इस घटना पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने सवाल उठाया कि आखिरकार डीटीसी की बसों में बार बार आग लगने की घटनाएं क्यों हो रही है। डीटीसी और दिल्ली सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है। यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी और महामंत्री मनोज शर्मा ने आरोप लगाया कि बसों की देखरेख में घोटाला होता है।

कई बार कंपनी के बजाय दूसरे लोकल पार्ट्स लगा दिए जाते हैं। कई बसों की मियाद खत्म हो चुकी हैं। यूनियन ने सवाल उठाया है कि इन बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र कौन और कैसे जारी कर रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह दिल्ली वासियों की जान के साथ खिलवाड़ है। यूनियन ने सभी डिपो में बसों के रखरखाव की जांच और उचित देखरेख की मांग की है। पिछले साल भी गर्मियों में बसों में आग लगने की घटनाएं हुई थी।

गैस सिलेंडर एक्सपायरी डेट पर रखें नजर, कैसे?

एसडी सेठी।

एनटीवी। खाना बनाने के लिए ज्यादातर घरों में रसोई गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हर महीने एलपीजी सिलेंडर भी खरीदते होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि सालों से इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के उपर लिखे कोड पर कभी किसी ने गौर नहीं किया होगा दरअसल घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस के सिलेंडर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। सिलेंडर के एक्सपायर हो जाने के बाद अगर उसमें एलपीजी गैस डाली जाए, तो वह गैस का दबाव सहन नहीं कर पाते है और जिसके कारण गर्मी बढने लगती है।और सिलेंडर के आग के नजदीक होने कारण वे कई बार ब्लास्ट भी कर जाते हैं। हालांकि बता दें कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट उसके ऊपर ही लिखी होती है।लेकिन अधिकतर कस्टमर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। यदि आपने गौर किया होगा कि गैस सिलेंडर पर ऊपर की और तीन पट्टियां बनी होती है।जिसमें से एक पर A-23, B-24, या फिर C-25 जैसे कुछ नंबर लिखे होते हैं। इन्हीं नंबरों को देखकर एक्सपायरी डेट का पता लगाया जा सकता है। एक्सपायरी डेट पता लगाने का तरीका जानें- ---

*1-अगर आपके सिलेंडर पर A लिखा है तो इसका मतलब वह जनवरी से मार्च तक के महीने दर्शा रहा है *

2-अगर B लिखा है तो वह अप्रैल से जून तक के महीने को दर्शा रहा है।

3-इसी तरह अगर सिलेंडर पर C लिखा हुआ है तो वह जुलाई से सितंबर को बता रहा है। ---

4- वहीं अगर सिलेंडर पर D लिखा है तो वो अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने को बता रहा है। इसके बाद आपने इन अल्फाबेट के आगे कुछ नंबर लिखे होते हैं।दरअसल वो नंबर सिलेंडर के एक्सपायर होने वाले साल के बारे में बताते हैं। जैसे अगर गैस सिलेंडर पर C-23 लिखा हुआ है, तो जानिये कि सिलेंडर साल 2023 में जुलाई से सितंबर महीने के बीच में एक्सपायर होगा। अब शायद जान गए होंगे कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को कैसे पता लगा सकते हैं, और किसी बडे हादसे से बच सकते हैं।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार

राजधानी में ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सी होगी बंद, एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान

एनटीवी संवाददाता

सरकार द्वारा जारी आदेश को नहीं मानने पर बाइक वालों और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों पर भी बड़ा जुर्माना लग सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों का चालान कटेगा। यही नहीं नियम का उल्लंघन करने वाले बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

वहीं सरकार ने बाइक टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी जारी की है कि अगर उन्होंने अपने एप पर बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इस नियम के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एग्रीगेटर्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी में है।

क्या कहता है परिवहन विभाग का आदेश

जो दो पहिया वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उनका वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार।

नियम के उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और गाड़ी जब्ती का भी प्रावधान।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द हो सकता है।

दिल्ली से पहले यह नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया जा चुका है। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। यह नियम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इस नियम का उद्देश्य सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित कराना है।

इनसाइड

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं.

इ

स आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को

एक समान नहीं होगी पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

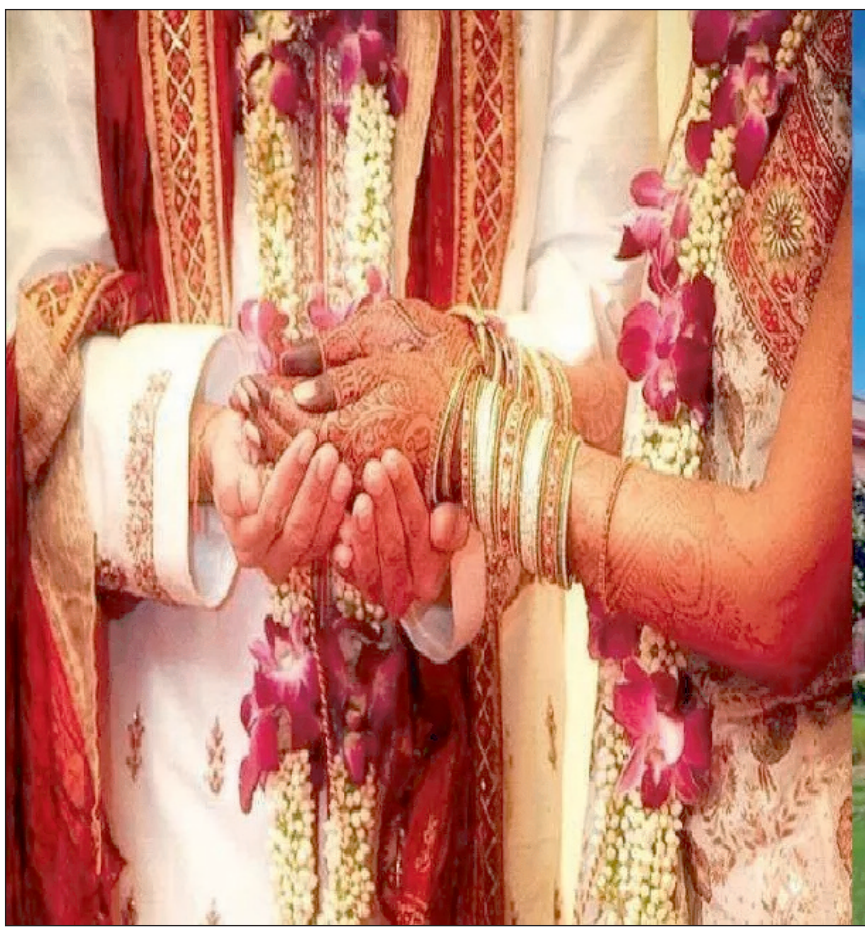

यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। इसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को एक समान करने की मांग की थी। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में शादी के लिए अलग आयु का निर्धारण किया गया है। यह व्यवस्था संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान न्यूनतम आयु की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो संसद के लिए आरक्षित हैं।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस दौरान यह भी कहा कि शीर्ष अदालत संसद को कानून बनाने के लिए परमादेश (एक असाधारण रिट) जारी नहीं कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले संसद के लिए हैं, हम यहां कानून नहीं बना सकते। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम संविधान के अनन्य संरक्षक हैं। संसद भी एक संरक्षक है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता चाहता है कि पुरुषों के बराबर होने के लिए महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए। इस प्रावधान को खत्म करने से महिलाओं के लिए शादी की कोई उम्र नहीं होगी। इसलिए याचिकाकर्ता एक विधायी संशोधन की मांग करता है। यह अदालत इसके लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती है। इसलिए हम इस याचिका को अस्वीकार करते हैं।गौरतलब है कि इस पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं।

याचिका में की गई है यह मांग

गौरतलब है कि यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। इसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को एक समान करने की मांग की थी। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में शादी के लिए अलग आयु का निर्धारण किया गया है। यह व्यवस्था संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर विवाह की आयु समान की जाए।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में शादी की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखी गई है। ऐसा इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के कारण हो रहा है। यह महिलाओं के साथ भेदभाव है। इसलिए उनके लिए शादी की आयु 18 साल को अवैध घोषित किया जाए। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि शादी की उम्र में अंतर लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय और महिलाओं की गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

शादी की न्यूनतम उम्र क्यों है?

बाल विवाह को अनिवार्य रूप से गैरकानूनी घोषित करने और नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कानून विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। भारत में 1978 से लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है।

SC ने 1996 के ड्रग जब्ती मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज की

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 1996 के ड्रग्स जब्ती मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा तय की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ ने संजीव भट्ट की ना केवल याचिका खारिज की बल्कि उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा कि 'तुच्छ' याचिका दायर करने के लिए उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने भट्ट को गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास राशि जमा करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस अदालत से संपर्क करने के बजाय मामले के शीघ्र निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करना चाहिए था। मामले को विस्तार देना निचली अदालत का मामला है।

Uniform laws: सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवाह, तलाक, विरासत और गुजारा भत्ता जैसे विषयों पर धर्म और लिंग-तटस्थ एक समान कानून बनाने का केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्या वह लैंगिक, धर्म-तटस्थ कानून बनाने के लिए विधायिका को निर्देश दे सकता है? पीठ ने कहा कि 'सवाल यह है कि अदालत इ न मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि ये मुद्दे विधायी डोमेन के अंतर्गत आते हैं।'

> सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत 'विवरण में नहीं जा सकती' जिसे बाद के चरण में देखा जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधायी डोमेन के भीतर आने वाले इन मुद्दों के संबंध में न्यायिक शक्तियों के दायरे के बारे में टिप्पणी की। साथ ही इस मुद्दे पर कई जनहित याचिकाओं सहित 17 याचिकाएं अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह तक स्थगित कर दी।

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से जहां तक मेरा संबंध है, सभी के लिए समान रूप से लागू लिंग-तटस्थ कानूनों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। न्यायिक पक्ष में क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करना आधिपत्य का काम है।

इससे पहले एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर प्रारंभिक आपत्ति है।

ताहिर हुसैन के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय करने में दखल देने से कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत 'विवरण में नहीं जा सकती' जिसे बाद के चरण में देखा जाएगा।

पीठ ने कहा, 'मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने के चरण में है। इसलिए हमें इस चरण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। यह स्पष्ट किया जाता है कि (निचली) अदालत इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का पालन करेगी।'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरु नानक से जुड़े मठ के ध्वंस पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से जुड़े एक मठ को गिराये जाने के मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि मठ का विध्वंस एक न्यायिक आदेश का उल्लंघन था।

न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका खारिज कर रही है। हम अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करना चाहते हैं। इसमें हमें अवमानना कार्यवाही शुरू करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया था कि 2019 में, शीर्ष अदालत ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र को साफ करते समय, अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मठ के देवता, समाधि, उसके अवशेष आदि तो हानि न पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अनावश्यक रूप से गरीब महिलाओं के गर्भाशय हटाए जाने (हिस्टेरेक्टॉमी) के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आरोप है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत उच्च बीमा राशि वसूलने लिए महिलाओं के गर्भाशय हटाए जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की मदद भी मांगी। पेशे से डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने मीडिया रिपोर्टों और शोधित तथ्यों के आधार पर जनहित याचिका दाखिल की है। इसके मुताबिक बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डॉक्टरों पर सरकार से उच्च बीमा शुल्क लेने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक 'हिस्टेरेक्टॉमी' करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजे और समस्या से निपटने के लिए सार्थक नीतिगत बदलावों की मांग की गई है।

क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए प्रोटीन? जानें डाइट में शामिल करने से क्या-क्या होते हैं फायदे

प्रोटीन के सेवन से आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है

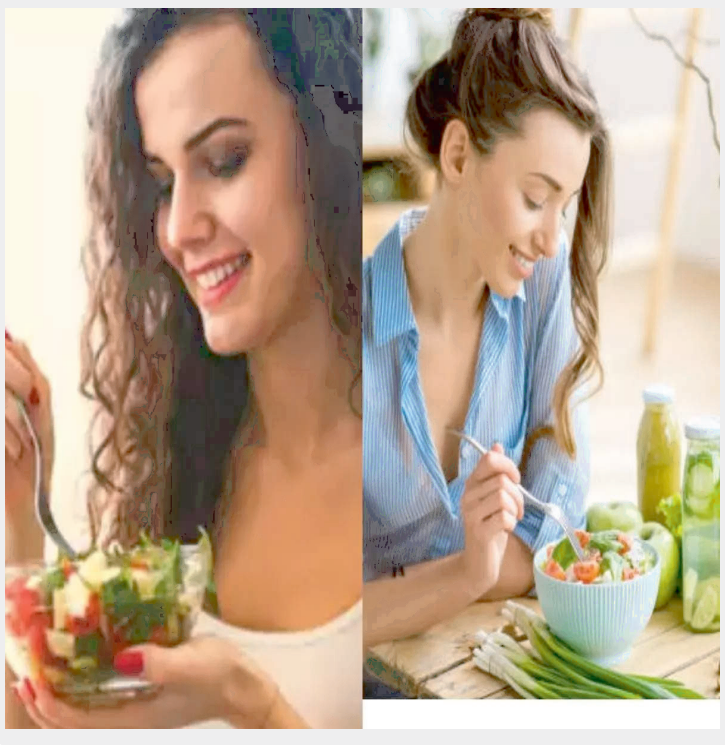

प्रोटीन के सेवन से देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं.प्रोटीन के सेवन से देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं.

प्रोटीन पुरुषों के साथ ही महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी होता है. इससे हेल्दी और फिट बॉडी लंबी उम्र तक बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही, प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और मसल्स फाइबर की मरम्मत के लिए भी जरूरी होता है. प्रोटीन एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो मसल मास और फिजिक को बनाए रखता है. महिलाओं के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत महत्वपूर्ण होता है. प्रोटीन की जरूरत उम्र, एक्सरसाइज लेवल, कैलोरी इनटेक और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है. चूंकि, शरीर सभी आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए सप्लीमेंट या डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करना चाहिए. प्रोटीन, वसा और कार्ब्स के विपरीत, स्टोर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में हर दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है.

महिलाओं के लिए प्रोटीन के फायदे

हेल्थकार्ट डॉट कॉम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटीन बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है. ये सभी केराटिन से बने होते हैं, जो एक तरह का संरचनात्मक प्रोटीन है. चूंकि, केराटिन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए शरीर में इसका निर्माण जारी रखने के लिए प्रोटीन युक्त फूड्स का सेवन करना जरूरी है. कोलेजन भी एक प्रोटीन है, जो हमारी त्वचा के वजन का 70% हिस्सा होता है. यह शरीर का सबसे प्रमुख प्रोटीन है, जो कनेक्टिव टिशूज में पाया जाता है. यह जोड़ों को स्थिर और गतिशील बनाए रखने में मदद करता है. प्रोटीन की कमी होने से समय से पहले त्वचा पर झुर्रियां पड़ सकती हैं.

मांसपेशियों को रखे मजबूत

महिलाओं के लिए प्रोटीन मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड में उच्च होता है और मांसपेशियों में ऐंठन को दूर करता है. इससे लीन मसल मास बनाए रखने में मदद मिलती है. महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस, अन्य हड्डियों की समस्या होने का रिस्क अधिक रहता है, ऐसे में उन्हें डायटरी प्रोटीन का सेवन अधिक करना चाहिए, ताकि मसल मास में इजाफा हो.

वजन होता है कम

प्रोटीन के सेवन से आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो वजन कम करना चाहती हैं. जिनका वजन बहुत अधिक है, वे यदि प्रोटीन ड्रिंक्स लेती हैं, तो इससे बॉडी वेट, फैट मास और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार होता है.

हड्डियां रहती हैं स्वस्थ

महिलाओं को हड्डियों से संबंधित समस्याएं बहुत होती हैं, ऐसे में सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी लेने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए प्रोटीन की भी जरूरत होती है. जब आप कम मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन करती हैं, तो प्रोटीन ही हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अध्ययनों के अनुसार, उच्च प्रोटीन आहार लेने से बोन मिनरल डेंसिटी का लेवल अधिक और हड्डियों के नुकसान की दर कम होती है.

इनसाइड

फरवरी में जून सी गर्मी: 55 साल में तीसरी बार सबसे गर्म दिन, विशेषज्ञों ने बताई तापमान बढ़ने की असली वजह

नई दिल्ली। फरवरी में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। रविवार को भी फरवरी में गर्मी का रिकॉर्ड बना था। तब तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। दिल्ली में गर्मी ने फरवरी माह में 55 साल में तीसरी बार रिकॉर्ड बनाया है। 1993 के बाद तीसरी बार फरवरी की गर्मी ने पसीने छुड़ाए हैं। फरवरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहने का ऑल टाइम रिकॉर्ड 26 फरवरी 2006 का है, तब तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि 1993 में 33.9 दर्ज किया गया था। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से नौ डिग्री अधिक 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के पीतमपुरा में तापमान 35 डिग्री के पार रहा, जबकि नजफगढ़ व पूसा में पारा 34.6 डिग्री दर्ज हुआ।

फरवरी में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। रविवार को भी फरवरी में गर्मी का रिकॉर्ड बना था। तब तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि फरवरी में दूसरी बार सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। अमूमन फरवरी इतनी गर्म नहीं होती है। फरवरी में ही तापमान इतना क्यों बढ़ रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि फरवरी में कोई भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ। इस कारण से बारिश भी नहीं हुई।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से बढ़ रहा तापमान

पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में ही विक्षोभ सक्रिय हुए लेकिन यहां उनका प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं अभी सूरज की तपिश भी सीधी ही धरती पर पड़ रही है, हवा की रफ्तार भी कम है। पश्चिमी हवा आ रही है लेकिन वो गर्म है। इस कारण से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या अभी लू की स्थिति है इस पर उन्होंने कहा कि जब 40 डिग्री से ऊपर होता है और तापमान की सामान्य वैल्यू काफी ज्यादा होने पर ही लू का प्रकोप होता है।

राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार अभी एक सप्ताह तक कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा, इस कारण से गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच बना रहने का अनुमान है। सोमवार को पीतमपुरा इलाके में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नजफगढ़ व पूसा में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

1969 से 2023 तक की फरवरी की गर्मी का रिकॉर्ड

वर्ष व दिन	अधिकतम तापमान
2006, 26 फरवरी	34.1 डिग्री सेल्सियस
1993, 17 फरवरी	33.9 डिग्री सेल्सियस
2023, 20 फरवरी	33.6 डिग्री सेल्सियस
2021, 26 फरवरी	33.2 डिग्री सेल्सियस
2017, 21 फरवरी	32.4 डिग्री सेल्सियस

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिर भेजा समन, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। इस मामले में मनीष सिसोदिया से पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है।

नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए फिर समन भेजा है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 26 फरवरी को सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जहां उनसे दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले 19 फरवरी सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन डिप्टी सीएम ने बजट बनाने के लिए समय मांगा था और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को एक हफ्ते का समय दिया था।

ईडी भी कर रही मामले की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पांच लोगों के अलावा सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र जनवरी में दाखिल किया था। ईडी की ओर से दायर दूसरे आरोपपत्र में भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया का नाम है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली व अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। ईडी अभी तक इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है। आबकारी नीति में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाए जाने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।

इस मामले में ईडी ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दाखिल किया गया था। अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है।

फरवरी में नहीं चलता पंखा: गर्मी से परेशान यात्रियों ने की दरख्वास्त, रेलवे ने दिया नियमों का हवाला

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर गर्मी से राहत देने वाले सभी पंखे इन दिनों बंद हैं। जबकि दिल्ली में गर्मी दस्तक देने लगी है।

नई दिल्ली। मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिल्ली में धीरे-धीरे पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में ट्रेन के मुसाफिर रात के वक्त एसी कोच में कूलिंग प्वाइंट कम करने की मांग करने लगे हैं। वहीं, स्टेशन के प्लेटफार्म पर पंखा चलाने की मांग भी बढ़ने लगी है। लेकिन रेलवे अपने नियम से मजबूर है। रेलवे का नियम यह है कि 15 मार्च के बाद ही प्लेटफार्म पर पंखा चलाने की अनुमति है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर गर्मी से राहत देने वाले सभी पंखे इन दिनों बंद हैं। जबकि दिल्ली में गर्मी दस्तक देने लगी है। ऐसे में सोमवार को कई युवा यात्री स्टेशन प्रबंधक से पंखा चलाने की मांग करने लगे। इसकी शिकायत भी की लेकिन उन्हें यह समझाया गया कि रेलवे का नियम यह कहता है कि फरवरी में पंखे नहीं चलते हैं। यात्री ने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो सांझा किया है जिसमें कहा है कि नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल है एक भी पंखा नहीं चल रहा है।

स्टेशन डायरेक्टर से जब शिकायत की गई तो रूखा जवाब मिला। कहा कि रेलवे बोर्ड का नियम है कि फरवरी में पंखे नहीं चलते, जाकर बोर्ड से पूछो ऐसे नियम क्यों बनाया है। हालांकि रेलवे का तर्क है कि सभी यात्री पंखा चलाने की मांग नहीं कर रहे है। कुछ यात्रियों की मांग पर चलाया भी जाए तो अन्य यात्री एतराज करेंगे। क्योंकि हर तरह के मुसाफिर प्लेटफार्म पर आते-जाते रहते हैं। बुजुर्ग यात्रियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। प्लेटफार्म नंबर एक पर जब कोई ट्रेन पहुंचती है तो वहां अन्य ट्रेन का इंतजार कर रहे बैठे यात्री परेशान होने लगते है। क्योंकि इस प्लेटफार्म पर हवा आने का रास्ता बंद हो जाता है।

बहरीन मेट्रो के पहले फेज के निर्माण का टेंडर हासिल करने के करीब पहुंची

एनटीवी संवाददाता

विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो अब विदेश में भी देश का मान बढ़ाने लगी है। इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) बहरीन मेट्रो परियोजना में अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के लिए प्री-क्वालिफिकेशन टेंडर प्रक्रिया में योग्य घोषित किया गया है।

नई दिल्ली। विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो अब विदेश में भी देश का मान बढ़ाने लगी है। इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) बहरीन मेट्रो परियोजना में अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के लिए प्री-क्वालिफिकेशन टेंडर प्रक्रिया में योग्य घोषित किया गया है। इसलिए दिल्ली मेट्रो बहरीन मेट्रो के पहले फेज के निर्माण का टेंडर हासिल करने के करीब पहुंच गई है।

डीएमआरसी को उम्मीद है कि दिल्ली मेट्रो बहरीन मेट्रो के निर्माण में न सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभाएगी, बल्कि उसका निर्माण भी कराएगी। साथ ही देश में निर्मित मेट्रो ट्रेनें बहरीन जाएंगी।

DMRC ने क्या कहा?

डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा कि बहरीन में पहले फेज में 30 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण होना है और 20 स्टेशन बनने हैं। इसके मद्देनजर डीएमआरसी ने बीईएमएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत बीईएमएल के पास मेट्रो के कोच तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं दिल्ली मेट्रो बहरीन मेट्रो परियोजना के निर्माण में भूमिका निभाएगी।

उल्लेखनीय है कि डीएमआरसी ने ढाका मेट्रो का निर्माण कराया था। इसके अलावा हाल ही में इजरायल मेट्रो के निर्माण की प्री-बिड टेंडर प्रक्रिया में दिल्ली मेट्रो ने सफलता हासिल की थी। इसके अलावा मिस्र, वियतनाम, और मारीशस की मेट्रो की प्री-क्वालिफिकेशन टेंडर प्रक्रिया में डीएमआरसी सफल रहा है।

बहरीन मेट्रो के पहले फेज के निर्माण का टेंडर हासिल करने के करीब पहुंची DMRC

एनटीवी संवाददाता

विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो अब विदेश में भी देश का मान बढ़ाने लगी है। इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) बहरीन मेट्रो परियोजना में अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के लिए प्री-क्वालिफिकेशन टेंडर प्रक्रिया में योग्य घोषित किया गया है। इसलिए दिल्ली मेट्रो बहरीन मेट्रो के पहले फेज के निर्माण का टेंडर हासिल करने के करीब पहुंच गई है।

डीएमआरसी को उम्मीद है कि दिल्ली मेट्रो बहरीन मेट्रो के निर्माण में न सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभाएगी, बल्कि उसका निर्माण भी कराएगी। साथ ही देश में निर्मित मेट्रो ट्रेनें बहरीन जाएंगी।

DMRC ने क्या कहा?

डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा कि बहरीन में पहले फेज में 30 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण होना है और 20 स्टेशन बनने हैं। इसके मद्देनजर डीएमआरसी ने बीईएमएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत बीईएमएल के पास मेट्रो के कोच तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं दिल्ली मेट्रो बहरीन मेट्रो परियोजना के निर्माण में भूमिका निभाएगी।

उल्लेखनीय है कि डीएमआरसी ने ढाका मेट्रो का निर्माण कराया था। इसके अलावा हाल ही में इजरायल मेट्रो के निर्माण की प्री-बिड टेंडर प्रक्रिया में दिल्ली मेट्रो ने सफलता हासिल की थी। इसके अलावा मिस्र, वियतनाम, और मारीशस की मेट्रो की प्री-क्वालिफिकेशन टेंडर प्रक्रिया में डीएमआरसी सफल रहा है।

न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान लंदन डायवर्ट, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लिया फैसला

एनटीवी संवाददाता

एयर इंडिया के एक विमान को लंदन डायवर्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक, विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था। रास्ते में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लंदन डायवर्ट करना पड़ा है। फ्लाइट का नंबर AI-102 बताया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित यात्री को विमान से उतारने के बाद विमान लंदन से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। हालांकि, स्थिति के बारे में विवरण तुरंत पता नहीं चल सका। विमान के पायलट के अनुसार, दिल्ली में उतरने से पहले उड़ान में कम से कम 6-7 घंटे की देरी होने की संभावना है।

इस बीच एयर इंडिया ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि विमान पर इमरजेंसी की स्थिति के कारण न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI-102 को लंदन डायवर्ट कर दिया गया है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे ग्राउंड स्टाफ को सतर्क कर दिया गया है। संबंधित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई है।

भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या हुई दोगुनी

इस बीच भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में करीब दोगुना इजाफा हुआ है। जनवरी में कुल 1.25 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की। जनवरी, 2022 में यह संख्या 64.08 लाख थी। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को कहा कि इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी लगातार पांचवें महीने गिरी है और यह 54.6 फीसदी रही है।

डीजीसीए के अनुसार, अगस्त में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 59.72 फीसदी थी। जनवरी में इसने 68.47 लाख यात्री ढोए थे। एअर इंडिया और विस्तारा ने 11.55 लाख और 11.05 लाख यात्री ढोए। गो फर्स्ट, एयर एशिया इंडिया से 10.53 लाख और 9.30 लाख यात्रियों ने यात्रा की। स्पाइसजेट से 9.14 लाख यात्री उड़ान भरे थे।

टाटा समूह की सभी एयरलाइंस से कुल 32.30 लाख यात्रियों ने जनवरी में यात्रा की थी। यह बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से 26 फीसदी है। एयर एशिया और एअर इंडिया पूरी तरह से टाटा की है जबकि विस्तारा में उसकी 51 फीसदी हिस्सा है।

लिंक रोड पर व्यस्त समय में ट्रैफिक हुआ जाम

डीएनडी लूप और लिंक रोड पर लगी वाहनों की कतार

एनटीवी न्यूज

सेक्टर-95 स्थित महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-14 चिल्ला बार्डर तक सोमवार को व्यस्त समय में सुबह करीब 10 बजे यातायात का दबाव रहा। सबसे अधिक समस्या डीएनडी लूप व लिंक रोड पर रही। करीब तीन किलोमीटर के दायरे में वाहन रेंगते रहे।

नोएडा। सेक्टर-95 स्थित महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-14 चिल्ला बार्डर तक सोमवार को व्यस्त समय में सुबह करीब 10 बजे यातायात का दबाव रहा। सबसे अधिक समस्या डीएनडी लूप व लिंक रोड पर रही। करीब तीन किलोमीटर के दायरे में वाहन रेंगते रहे। व्यस्त समय में जाम के कारण नोएडा से दिल्ली जा रहे चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल, कालेज, फैक्ट्री, दफ्तर जाने के लिए निकले लोग देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचे। नोएडा-दिल्ली कालिंदी कुंज बार्डर पर यातायात का दबाव रहा। शाम को व्यस्त समय में सेक्टर-62 माडल टाउन गोलचक्कर पर यातायात का दबाव अधिक होने से यातायात का दबाव रहा।

बाटेलनेक पर रोक कराया चलाया ट्रैफिक

बाटेलनेक पर जाम को खत्म करने के लिए अब संबंधित जगह पर व्यस्त समय में ट्रैफिक रोककर चलाया जाएगा। अभी सेक्टर-16 ए फिल्म सिटी, सेक्टर-62 माडल टाउन गोल चक्कर, सेक्टर-121 पर्थला चौक, किसान चौक, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे अंडरपास निर्माण वाले स्थल, सेक्टर-95 महामाया फ्लाईओवर, दलित प्रेरणा स्थल, सेक्टर-56 के पास बाटेलनेक बनने के कारण व्यस्त समय में जाम लगता है। इन जगह पर वायु प्रदूषण भी बढ़ा हुआ रहता है।

यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई

महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन सेक्टर-49 में शिक्षकों व विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के विषय में एवं यातायात नियमों व संकेतों के प्रति जागरूक किया गया। अपना घर सोशल वेलफेयर सोसायटी सेक्टर-49 में शिक्षकों व बच्चों को यातायात नियमों व संकेतों के प्रति जागरूक किया गया।

कालेज जा रही छात्रा के साथ मनचले ने की मारपीट, तेजाब डालने की धमकी; पुलिस में रिपोर्ट दर्ज

गाजियाबाद के क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाले छात्रा को एक मनचला परेशान कर रहा है। वह दोस्ती न करने पर चेहरे पर तेजाब डालकर जिंदगी तबाह करने की धमकी देता है। अब मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाले छात्रा को एक मनचला परेशान कर रहा है। वह दोस्ती न करने पर चेहरे पर तेजाब डालकर जिंदगी तबाह करने की धमकी देता है। आरोप है कि मनचले ने कालेज जाते समय उनके साथ सड़क पर मारपीट की और बाल पकड़कर खींचे।

रास्ते में करता है अश्लील कमेंट

पीड़ित छात्रा का कहना है कि आरोपित काफी समय उनका पीछा कर रहा है और रास्ते में अश्लील कमेंट करते हुए छेड़छाड़ करता है। पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि उनकी बेटी एक कालेज में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है।

जबरदस्ती दोस्ती का बना रहा दबाव

उसी के कालेज में पढ़ने वाला शिवम उनकी बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा है। वह कालेज आते-जाते हुए बेटी का पीछा करता है और अश्लील कमेंट कर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। आरोपित उनकी बेटी पर जबरन दोस्ती का दबाव बना रहा है।

मना करने पर तेजाब फेंकने की दी धमकी

आरोप है कि शिवम ने कालेज जाते समय रास्ते में उनकी बेटी पर जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाया। मना करने पर उसने बेटी के बाल पकड़कर मारपीट की और चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा आरोपित से बुरी तरह से डरी हुई है। एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इनसाइड

स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूटे, गन पॉइंट पर वारदात को दिए अंजाम

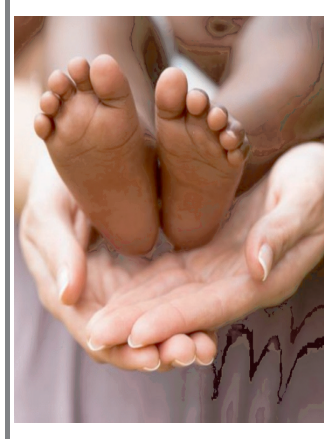

साहिबाबाद में एक स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने गन पॉइंट पर 5 लाख रुपए लूट लिए। स्क्रैप कारोबारी शनिवार की देर रात फैक्ट्री से घर को वापस लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।

साहिबाबाद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कारोबारी की स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने 5 लाख रुपए की लूट की है। कारोबारी की शालीमार गार्डन में स्क्रैप की फैक्ट्री है। बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी को गोली मारने की धमकी देते हुए रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

फैक्ट्री से घर को लौट रहा था कारोबारी

पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत कराई है। बता दें साहिबाद के शालीमार गार्डन में एक स्क्रैप फैक्ट्री है। फैक्ट्री से रात के समय स्क्रैप कारोबारी अनस मलिक वापस घर लौट रहा था। अनस के पास रुपयों से भरा बैग था। फैक्ट्री से लौट रहे कारोबारी का बदमाशों ने पीछा किया।

5 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश

कारोबारी अनस मलिक के अनुसार, शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे कार से घर जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पहले ही एक कार में चार बदमाश आए और ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी। अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।

दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, ससुर पर छेड़खानी का आरोप, पति समेत 5 पर केस

मोदी नगर में दहेज में कार नहीं मिलने पर ससुरालियों द्वारा विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। ससुर पर भी छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

मोदीनगर। दहेज में कार नहीं मिलने पर ससुरालियों द्वारा विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। ससुराल के लोग लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। ससुर पर भी छेड़खानी का आरोप है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर भोजपुर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

दहेज और कार की मांग कर रहे ससुराली जन

विवाहिता फिलहाल अपने मायके भोजपुर के एक गांव में रह रही है। भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति किसान हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अप्रैल 2022 में नोएडा में थी। शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन ससुराल के लोग शादी में मिले दान-दहेज से खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज व कार की मांग करते थे।

शादी के बाद ही विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा

शादी के महीने भर बाद से ही विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। आए दिन ससुराल के लोग उन्हें पीटते, लेकिन पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का हवाला देते हुए हर बार विवाहिता दहेज से मना कर देती। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ समय बाद ससुराल के लोग दहेज मांगना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवाहिता की प्रताड़ना और बढ़ गई।

ससुर पर छेड़खानी का लगा है आरोप

आरोप है कि ससुर भी उनपर गलत नजर रखता था। कई बार छेड़खानी भी कर चुका था। जब इस बारे में विवाहिता ने पति को बताया तो आरोपित ने उल्टा उन्हें ही गलत ठहराया। कुछ दिन पहले आरोपितों ने विवाहिता को बेल्ट व लाठी-डंडों से पीटकर घर से निकाल दिया। दहेज लाने पर ही घर आने की चेतावनी दी। विवाहिता अपने घर भोजपुर पहुंची और स्वजन को सारी बात बताई।

पति समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज

इसके बाद पंचायत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। परेशान होकर विवाहिता ने भोजपुर पुलिस को सारी बात बताई। आरोपितों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। इस मामले में एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी का कहना है कि तहरीर के आधार पर पति समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

दिल्ली-NCR से होली पर घर जाने वाले नहीं होंगे परेशान, लखनऊ-कानपुर रूट पर 24 घंटे चलेंगी बसें

होली के मौके पर दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से लखनऊ कानपुर और गोरखपुर अपने-अपने घर जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे बसें चलाई जाएंगी जिससे यात्रियों को त्योहार पर अपने घर पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

नई दिल्ली/ नोएडा। दिल्ली से लगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो होली के त्योहार पर गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ के लिए भी बसें चलाएगा। इसके साथ ही बदायूं, मैनपुरी, एटा, आगरा, अलीगढ़ व अन्य जिलों के लिए चल रही बसों के चक्करों को भी बढ़ाएं जाएंगे। इसके साथ ही लोकल रूट पर चल रही बसों के भी चक्करों को बढ़ाएं जाएंगे।

होली के एक सप्ताह पहले से ही ग्रेटर नोएडा डिपो की बसों की सेवाओं का लाभ यात्रियों को मिलने लगेगा। कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर के लिए चलने वाली बसें यात्रियों की उपलब्धता पर परीचौक से भी संचालित की जाएंगी। इसके अलावा आनंद विहार और कौशांबी बस अड्डे से भी बसों का संचालन होगा।

वहीं, नालेज पार्क में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को परी चौक से ही अपने गंतव्य पर जाने के लिए बसें मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा डिपो के स्टेशन अधीक्षक विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि होली के त्योहार से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई हैं।

तैयार किए जा रहे हैं बसों के रूट

बसों के रूट चार्ट तैयार किए जा रहे है। लंबे रूट जैसे लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर की बस में दो-दो चालकों की ड्यूटी लगाई जाएंगी। इसके साथ अन्य रूट पर चलने वाली बसों के भी फेरे बढ़ाएं जाएंगे। त्योहार पर ग्रेटर नोएडा डिपो की ओर से बसों का संचालन 24 घंटे किया जाएगा। यात्रियों को किसी भी प्रकार की घर पहुंचने में असुविधा न हो, इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। परीचौक से मिलेगी हर रूट के लिए बसें आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बुलंदशहर के अलावा अन्य जनपदों के लिए जाने वाली बसें यात्रियों को परी चौक से ही मिलेगी।

एप से बुक हो सकेगी टिकट

यात्रियों को कोई यात्रा करने में परेशानी न हो इसके लिए डिपो के सभी 134 बसों को लगाया जाएगा। इसके साथ ही परी चौक पर डिपो के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएंगी। एप से भी बुक कर सकते हैं टिकट ग्रेटर नोएडा डिपो की बसों में यात्रा करने के लिए एप से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा डिपो की 17 बसें नोएडा से आगरा, नोएडा से चंदौसी, नोएडा से बदायूं के अलावा अन्य रूट पर संचालित होती है। यह सभी बसें नोएडा से ही चलेगी।

होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा डिपो से चलाई जा रहीं बसों के बारे में बताते हुए एआरएम ललित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि होली के त्योहार के एक हफ्ते पहले से 24 घंटे बसों का संचालन किया जाएगा। हर रूट पर कितनी बसों का संचालन होगा इसका चार्ट तैयार किया जा रहा है।

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

ऑटोमोबाइल विशेष

इनसाइड

परिवार की सुरक्षा से न करें खेलवाड़, कार लेने से पहले जरूर चेक करें ये 5 सेफ्टी फीचर्स

अगर आप इन दिनों एक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। किसी भी कार में इन टॉप-5 सुरक्षा फीचरों को जरूर होना चाहिए।

नई दिल्ली। हम में से ज्यादातर लोग जब कभी भी नई कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस और सुरक्षा से जुड़े फीचर्स पर ध्यान देते हैं। पहले जहां कार के डिजाइन, लुक और पावरट्रेन को भारत में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब ग्राहक इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं कि उनकी कार हर तरह से सुरक्षित रहें और चालक के साथ-साथ पैसेंजर को भी सुरक्षा पहुंचाए। सेफ्टी फीचर्स के लिए लोग अधिक से अधिक रकम चुकाने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि, बहुत कम लोगों को पता होता है कि असल में उनकी गाड़ी पर कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए। इसलिए, आज हम आपको 5 ऐसे सेफ्टी कार फीचर्स (Safety Car Featurers) के बारे में बताएंगे जिनका होना बेहद जरूरी है।

1. एयरबैग (Airbags)

कार चाहे सस्ती हो या महंगी, उसमें एयरबैग का होना बेहद जरूरी है। यह दुर्घटना के समय एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को कम करता है और चालक के साथ-साथ पैसेंजर की जान को भी बचाता है। वर्तमान में भारत में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियों में डुअल एयरबैग होता है, लेकिन अब सरकार ने 6 एयरबैग का होना कार में जरूरी कर दिया है।

2. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)

आजकल की गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर EBD के साथ ABS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ABS या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अचानक ब्रेक लगाने पर कार को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी के पहिये लॉक हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए ABS बहुत मददगार साबित होता है।

3. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC)

ओवरस्टेयर या अंडरस्टेयर के कारण कई बार कार अपना नियंत्रण खो देती। इससे बचने के लिए आपात स्थिति के दौरान ईएससी ब्रेक लगाता है और इंजन की पावर को संतुलित करता है।

4. एडजस्टेबल स्टीयरिंग

बहुत बार स्टीयरिंग व्हील और चालक के बीच की दूरी और ऊंचाई सही नहीं रहने के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, जो बाद में जाकर दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इस वजह से एडजस्टेबल स्टीयरिंग का कार में होना बेहद जरूरी है। यह ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील की ऊंचाई और ड्राइवर से दूरी को ठीक रखने में मदद करता है।

5. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

बेहतर कंट्रोल और ईंधन की बचत के लिए आजकल की गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को लगाया जाता है। यह कार के हर पहिये पर लगा होता है जो कि एक सेंसर के जरिए डैशबोर्ड तक सूचनाओं को भेजता

क्या सच में गायब हो जाएंगी पेट्रोल कारें? EV या हाइड्रोजन; कौन बनेगा ऑटोमोबाइल का भविष्य

Petrol Car की जगह लेने के लिए कंपनियां तेजी के साथ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों को पेश कर रही हैं। ऐसे में क्या सच में इस तरह की गाड़ियां की भविष्य में मिलेंगी इस बात से पहले इनके फायदे और नुकसान को समझ लें।

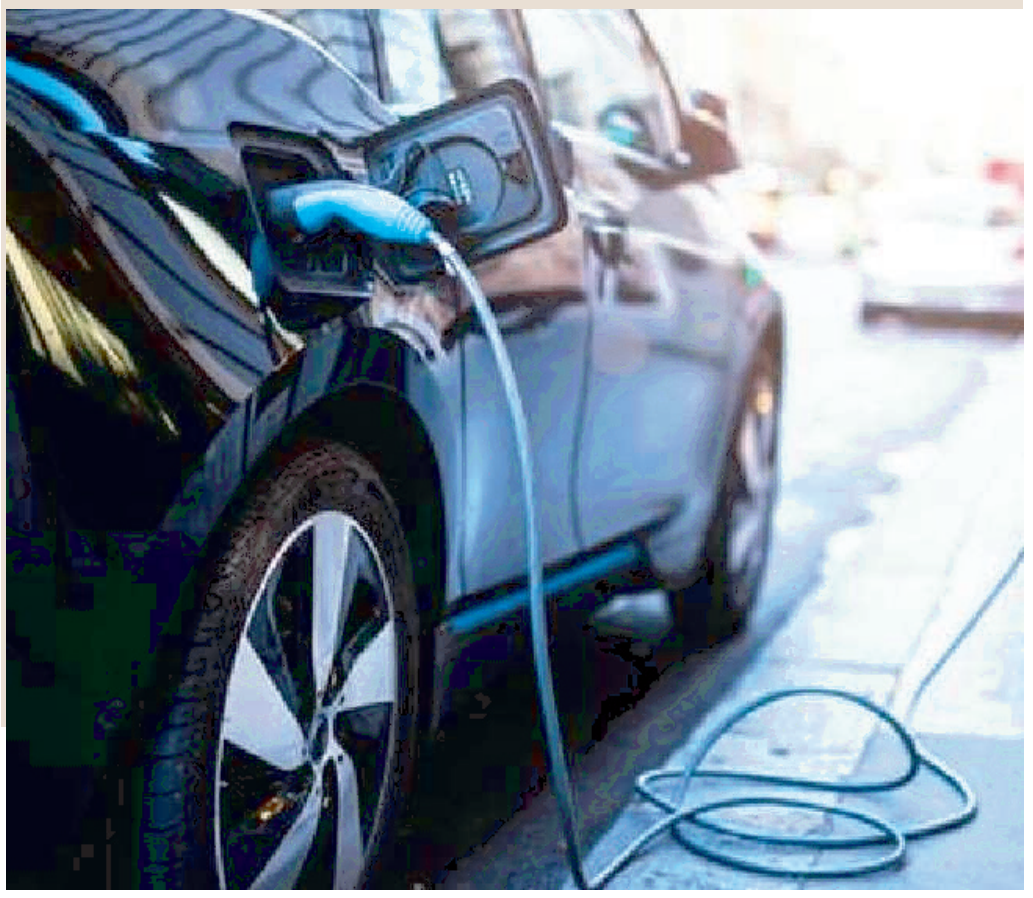

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ ICE इंजनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन्ही कारणों से वाहन निर्माता कंपनियां ईंधन के नए विकल्पों की तलाश कर रही हैं। बीते कुछ साल में विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन खूब बढ़ा है। यह सस्ता और कम नुकसानदायक विकल्प है। वहीं, अब एक नया हाइड्रोजन विकल्प भी सामने आया है।

हाल में हुए Auto Expo 2023 में MG Motors ने अपनी हाइड्रोजन कार Euniq 7 को पेश किया, जो हाइड्रोजन सेल के अलावा कई और खूबियों से लैस थी। वहीं, Toyota ने पहले ही अपनी Mirai कार के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश कर दिया है।

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों ही गाड़ियों को भविष्य की गाड़ी के रूप में देखा जा रहा है और ये दोनों ही पेट्रोल कारों की जगह ले सकती है। पर सवाल उठता है कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक दोनों में से कौन-सी कार ज्यादा सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद साबित होगी? इसलिए, आज हम इन दोनों की एक तुलना करने जा रहे हैं।

कौन-सी कार में मिलेगी ज्यादा रेंज

इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोजन कारों में रेंज ज्यादा मिलने वाली है। हाइड्रोन कारों का धनत्व ज्यादा होता है, जिससे ये कारें दूर तक चलाई जा सकती है। वर्तमान में पेश किए गए मॉडलों के आधार पर टोयोटा मिराई को एक बार चार्ज करने पर 600 किमी तक की रेंज दे सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में अब तक अधिकतम 250 किमी तक की रेंज देखई गई है।

बजट फ्रेंडली

ज्यादा रेंज के साथ ही गाड़ियों को बजट फ्रेंडली भी होना जरूरी है। इस आधार पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट में ज्यादा आसानी से आ सकती है, जबकि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों में लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से इनकी कीमतें भी अधिक होंगी। वहीं, बाद के समय में कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन कारों को कम कीमत पर लाना होगा।

रिफिल में लगने वाला समय

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों गाड़ियां को अगर पेट्रोल गाड़ियों की जगह लेनी है तो इसे रिफिल करने में कम समय लगना चाहिए। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक कारों अगर एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इसे फुल चार्ज होने में 4 से 8 घंटे का समय लगता है। वहीं, हाइब्रिड कारों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। फ्यूल स्टेशन पर एक किलो हाइड्रोजन को रिफिल करने में बस 5 से 10 मिनट कसमी लगता है, जो काफी हद तक पेट्रोल रिफिलिंग के समान ही है।

दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी पंजीकरण होगा आसान, सरकार जल्द करेगी ये व्यवस्था

MoRTH ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शर्तों में एक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होना अनिवार्य है जो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ ड्राइवर को काम पर रखा हो।

नई दिल्ली। भारत सरकार दिव्यांग लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसी क्रम में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों से दिव्यांगजन कैटेगरी में आने वाले लोगों को जरूरी टेक्स लाभ की गुजारिश की है। अभी तक केवल नए वाहन खरीद पर यह लाभ मिलता था।

केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में मेंशन किया है कि दिव्यांग व्यक्ति जो वाहन के मालिक हैं और ड्राइवर को किराए पर लेते हैं, उन्हें ₹दिव्यांगजन₹ श्रेणी के तहत वाहन पंजीकरण प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वाहन का स्वामित्व ₹दिव्यांगजन₹ श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए निर्णायक कारक होगा। इससे वाहन गाड़ी का प्रकार। MoRTH ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, शर्तों में एक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होना अनिवार्य है जो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ ड्राइवर को काम पर रखा हो। दूसरी शर्त यह है कि अगर दिव्यांगजन नई गाड़ी खरीदने में असमर्थ है और वह इस कैटेगरी से आवेदन करता है तो उसका पंजीकरण मान्य होगा। इसके अलावा भी सर्कुलर में कई निर्देश दिए गए हैं।

इंडियन मार्केट में कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स क्यों फेमस? असल वजहों के बारे में समझें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां बेचे गए कुल वाहनों की अधिकांश बिक्री पैसेंजर वाहनों द्वारा कवर की जाती है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों का हैं। कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स को लोग अधिक महत्व देते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इस समय कारों की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। आप खुद ही आप पास के घरों में खड़ी कारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि, जिनके भी घर कार होगी उनके घर दोपहिया वाहन जरूर देखने को मिलेगा। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं उन 3 वजहों के बारे में जहां आपको यह पता चलेगा कि कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स इंडियन मार्केट में क्यों फेमस हैं

बेहतरीन माइलेज

कारों की तुलना में मोटरसाइकिल की माइलेज भी अधिक होती है। अगर कार औसतन 25 की माइलेज देती है तो टू-व्हीलर भी 60-70 तक की औसतन माइलेज देने में सक्षम है। यही वजह है कि भारत में अधिकतर लोग चार पहिया की तुलना में दोपहिया वाहन खरीदना अधिक पसंद करते हैं। इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आने वाली मोटरसाइकिलों जिसमें अधिक सीसी का इंजन लगा हुआ होता है उसकी औसतन माइलेज 20-30 Kmpl होती है।

प्रदूषण

पर्यावरण के नजरिए से भी दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन की तुलना में बेहतरीन होते हैं, क्योंकि चार पहिया वाहन अधिक ईंधन खाते हैं और उससे अधिक पॉल्यूशन भी निकलता है, वहीं दोपहिया वाहन हैं बहुत कम ईंधन खर्च होने के कारण उससे होने वाली पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है। इसलिए, पर्यावरण के लिहाज से टू-व्हीलर बेस्ट होती हैं।

किफायती दाम

दोपहिया वाहन कार की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं। जिस वजह से एक मध्यम वर्गीय परिवार और निचला मध्यम वर्गीय परिवार भी इसे खरीद पाता है। भारत के बाज़ार में लगभग 40,000 रुपए की शुरुआती क़ीमत से दोपहिया वाहनों की बिक्री शुरू हो जाती है। इसके अलावा, इन वाहनों के लिए बीमा बहुत कम लागत पर आता है। दोपहिया वाहनों की सबसे ख़ास बात यह होती है कि इनकी री सेल क़ीमत भी बहुत अधिक होती है। साथ ही इनका माईलेज भी कार की तुलना में कहीं बेहतर होता है।

इस मौसम में सबसे अधिक परेशान करती है कार के अंदर की धुंध, इन उपायों से मिलेगा चुटकियों में समाधान

आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। इससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

नई दिल्ली। इस समय ठंड काफी तेजी से बढ़ रही है।सुबह के समय कोहरा काफी अधिक हो रहा है, जिससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये परेशानी कार के अंदर भी होती है। अगर आपके कार के अंदर भी ठंड के मौसम में धुंध भर जाती है तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। सबसे अधिक दिक्कत इस समय होती है। कोहरे के कारण आप कार के बाहर का देख नहीं सकते हैं। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें

अगर आप इस बात से अनजान हैं तो अपनी कार के अंदर आप विंडशील्ड को डिफॉग करने के लिए गाड़ी के अंदर दिए गए डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें। ये बटन आपके कार के अंदर आता है। इसको दबाने के बाद हवा सीधे विंडशील्ड तक पहुंच जाती है।

एसी को ऑन करें

कार में जैसे ही बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद फॉग महसूस होने लगता है, जिसके कारण आप बाहर का देख नहीं सकते और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आप कार में एसी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद लिंट-फ्री कपड़े से स्क्रीन को पोछ लेना चाहिए, ताकि आपको दिखाई देने लगे। इसके कारण कार के अंदर की धुंध भी गायब हो जाती है।

खिड़की को नीचे करें

कार के अंदर से धुंध को बाहर करने के लिए खिड़की को नीचे करना एक अच्छा ऑप्शन है। इससे बाहर की हवा अचानक आपकी कार के अंदरुनी हिस्सो को भर देती है, इसके कारण ही अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तरह हो जाता है।

भारत को अगुआ बनाएंगे प्रवासी भारतीय

डा. जयंतीलाल भंडारी

ज्ञातव्य है कि दुनिया में भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा डायस्पोरा है जिसकी संख्या लगभग 3.2 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या 1.79 करोड़ तक पहुंच गई। प्रवासियों की यह संख्या वर्ष 1990 में 66 लाख के मुकाबले छलांगे लगाकर तेजी से बढ़ी है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यह रेखांकित हुआ कि भारतवंशी और प्रवासी भारतीय वैश्विक तंत्र का अद्वितीय और अहम हिस्सा हैं।

यकीनन पिछले माह जनवरी में संपन्न हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद प्रवासी भारतीय दुनियाभर में भारत को अगुआ बनाए जाने के अभियान में जुट गए हैं। ज्ञातव्य है कि 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में बड़े ही भव्य रूप में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभूतपूर्व रहा है। इस प्रवासी सम्मेलन में शामिल करीब 70 देशों के 3500 से अधिक प्रतिनिधियों का यह स्वर सम्मेलन के दौरान लगातार गूंजता रहा कि आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत ने 75 साल का संतोषजनक सफर तय किया है और तेजी से आगे बढ़ते सामथ्र्यवान भारत पर प्रवासियों को गर्व है। इस सम्मेलन में शामिल आईटी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त, फॉर्मा, ऑटोमोबाइल्स, एजुकेशन आदि के क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भारत के साथ आर्थिक सहयोग, ज्ञान-कौशल सहभागिता को बढ़ावा देने और देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश और विश्व गुरू बनाने में अहम भूमिका निभाने का संकल्प लेते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के अभिन्न अंग हैं। जहां भारत के विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका है, वहीं भारत ने अपने प्रवासियों को ताकत देने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अगले 25 वर्षों के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय को वैश्विक स्तर पर भारत को अगुआ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विदेशों में अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने और अपनी अलग पहचान बनाने वाले 57 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया। निःसंदेह 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन पिछले प्रवासी भारतीय सम्मेलनों की तुलना में अधिक प्रभावी व अधिक लाभप्रद रहा है।

ज्ञातव्य है कि दुनिया में भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा डायस्पोरा है जिसकी संख्या लगभग 3.2 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या 1.79 करोड़ तक पहुंच गई। प्रवासियों की यह संख्या वर्ष 1990 में 66 लाख के मुकाबले छलांगे लगाकर तेजी से बढ़ी है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यह रेखांकित हुआ कि भारतवंशी और प्रवासी भारतीय वैश्विक तंत्र का अद्वितीय और अहम हिस्सा हैं। वे शासन-प्रशासन, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, कारोबार, प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में दुनिया की अगुवाई कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय भारत की महान पूंजी हैं। प्रवासी भारतीय विश्व के समक्ष भारत के वास्तविक राजदूत हैं और भारत का चमकता हुआ चेहरा हैं। साथ ही ये विश्व मंच पर भारत के हितों के हिमायती भी हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारतीय प्रवासी भारत को धन भेजने के मामले में अन्य सभी देशों के प्रवासियों से बहुत आगे हैं। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलमपेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के मुताबिक विदेश में कमाई करके अपने देश में धन (रेमिटेंस) भेजने के मामले में वर्ष 2022 में भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे आगे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में प्रवासी भारतीयों के द्वारा भेजी जाने वाली रकम करीब 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 2021 में प्रवासियों ने 87 अरब डॉलर की धन राशि स्वदेश भेजी थी। प्रवासियों से धन प्राप्त करने वाले दुनिया के विभिन्न देशों की सूची में भारत वर्ष 2008 से अब तक पहले क्रम का देश बना हुआ है। कोविड महामारी के बाद यह माना जा रहा था कि विदेश से लौटे प्रवासी वापस नहीं जाएंगे, लेकिन यहां से ज्यादा लोग विदेश गए और उन्होंने भारत के लिए अपना सहयोग और अधिक बढ़ाया।

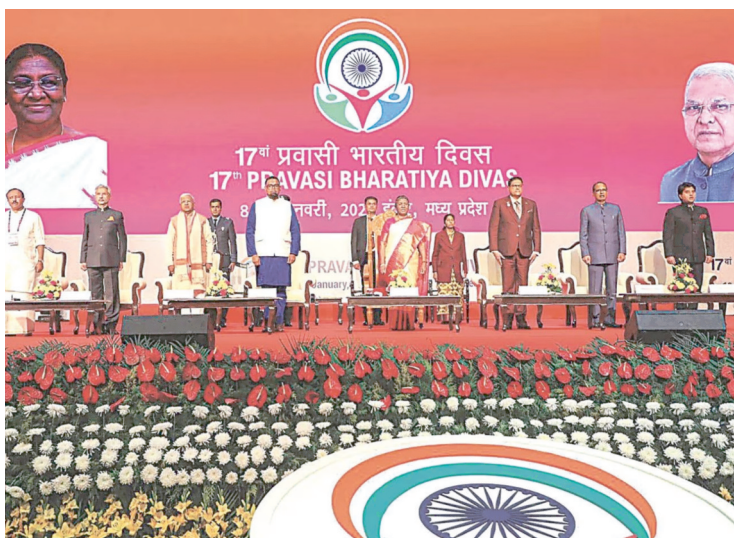

विगत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर वाशिंगटन में अमेरिका के भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीयों से सम्बद्ध अन्य सभी देशों के प्रवासियों से गैर-लाभकारी संस्थाओं के एक संयुक्त संगठन इंडिया फिलांथ्रोपी अलायन्स (आईपीए) के तत्वावधान में भारत के विकास और मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आर्थिक मदद दिए जाने का निर्णय विभिन्न देशों के प्रवासी भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायी बन गया है। आईपीए ने 2 मार्च 2023 को इंडिया गिविंग डे मनाने का निश्चय किया है। अभी तक आईपीए जिस तरह भारत को सहयोग के लिए सालाना करीब एक अरब डॉलर जुटाता है, उसे अगले साल बढ़ाकर 3 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अतीत में जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई तब प्रवासियों ने मुक्त हस्त से भारत के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में सहयोग दिया है। जब वर्ष 1998 में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पोखरण-2 विस्फोट के बाद अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के द्वारा भारत पर लगाए गए तब आर्थिक प्रतिबंधों को वापस कराने में प्रवासी भारतीयों ने देश का सबसे ज्यादा साथ दिया और दुनिया का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने हेतु अगस्त 1998 में रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स की मदद से 4.8 अरब डॉलर की राशि जुटाई गई थी। इसी तरह 2001 में इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट स्कीम की मदद से करीब 5 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटाई गई। ऐसे प्रयासों से विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताएं कम हुई थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के समय दुनिया के विभिन्न देशों में चिंता और अनिश्चितता के दौर में फंसे भारतीयों को प्रवासी भारतीयों का हर तरह से साथ मिला था।

इस तरह वर्ष 2021 की कोरोना संक्रमण की दूसरी दर्दनाक लहर के बीच भारतीय प्रवासियों ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मजबूत करने के लिए बेमिसाल सहयोग दिया। 17वें प्रवासी सम्मेलन में यह बात भी उभरकर सामने आई कि अब जहां प्रवासी भारतीय भारत को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता और अधिक बढ़ाएंगे, वहीं भारत को भी प्रवासियों के दुख-दर्द में अधिक सहभागी बनना जरूरी होगा। हमें प्रवासियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण में अहम भूमिका निभाना होगी। वस्तुतः दुनिया के सारे प्रवासी भारतीय बहुत धनी नहीं हैं। अधिकांश देशों में कोविड-19 के बाद इनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से विभिन्न खाड़ी देशों में लाखों कुशल-अकुशल भारतीय श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और जीवन के लिए जरूरी उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हरसंभव मदद करना होगी। दुनिया के कई देशों में कार्यरत भारतीय एम्बेसी और हाई कमीशन के द्वारा भारतीयों के साथ अच्छे व्यवहार की भी जरूरत बनी हुई है। हम उम्मीद करें कि 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों के साथ स्नेह, सहयोग और आपसी विकास के नए, असाधारण एवं अभूतपूर्व अध्याय दिखाई देंगे। हम उम्मीद करें कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद भारतीय प्रवासियों से एक बार फिर देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के साथ-साथ गरीबी, भूख की चुनौती, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य व शिक्षा की बड़ी चुनौतियों के निराकरण और देश में डिजिटल नई पीढ़ी तैयार करने के लिए अधिक सहयोग मिलेगा। हम उम्मीद करें कि जिस तरह तीन दशक पहले चीन के प्रवासियों ने चीन की चमकीली आर्थिक तस्वीर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उसी तरह प्रवासी भारतीय वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में भूमिका निभाएंगे।

संपादक की कलम से

मोदी विरोध का विदेशी चेहरा

हंगरी मूल के अमरीकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस बुनियादी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कट्टर विरोधी रहे हैं। अडानी समूह में मौजूदा गड़बड़ी और संकट तो महज एक परदा है। उसकी आड़ में सोरोस प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अभी ही भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान नहीं छेड़ा है, बल्कि 2014 से ही यह सिलसिला टुकड़ों-टुकड़ों में जारी रहा है। आश्चर्य है कि अमरीकी कारोबारी ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। वह हमारे लोकतंत्र का आकलन करने वाला कौन है? इस 92 वर्षीय बूढ़े वामपंथी की सोच, पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि वह भारत के ही कुछ तबकों, शहरी नक्सलियों और वामपंथी बुद्धिजीवियों में सेंध लगाता रहा है। उनकी आर्थिक मदद करता है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभियानों को 'हवा' देता है। ऐसी देश-विरोधी, विध्वंसक हरकतें उसके संगठन करीब 70 देशों में करते रहे हैं।

जॉर्ज अपने मानस के मुताबिक दुनिया का विमर्श तय करना चाहता है। इसे सनक नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे! सोरोस 2024 के चुनावी जनादेश को प्रभावित कर मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने के मंसूबे पाले बैठा है। उसका मानना है कि यदि 2024 में सत्ता-परिवर्तन होता है और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को जनादेश हासिल होता है, तो भारत में लोकतंत्र का पुनरोत्थान हो सकता है। हमारा सवाल है कि भारत में लोकतंत्र को क्या हुआ है? उसके संकट और चुनौतियां क्या हैं? क्या भारत में लोकतंत्र के पुनरोत्थान की कोई गुंजाइश है? बहरहाल 70,000 करोड़ रुपए के अमरीकी कारोबारी और उसके एनजीओ भारत में सक्रिय होकर, भारत के ही खिलाफ, कोई साज़िश रचें या दुष्प्रचारों को 'हवा' दें, तो उसे सरकार के स्तर पर बर्दाश्त क्यों किया जा सकता है? या इतने लोकतांत्रिक लचीलेपन और विनम्रता की जरूरत ही क्या है? सोरोस का एनजीओ है-'ओपन सोसायटी फाउंडेशन।' इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, लेकिन भारत में इसका प्रवेश 1999 में हुआ। 2016 में मोदी सरकार ने ही इस एनजीओ को 'वॉच लिस्ट' में रखा था, क्योंकि संगठन पर भारत को अस्थिर करने के गंभीर आरोप लगे थे। दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि जॉर्ज सोरोस के हस्तक्षेप से जो भारत-विरोधी रपटें या सूचकांक तैयार किए जाते रहे हैं, उन्हें भारत में कांग्रेस एकदम लपक लेती है और फिर दुष्प्रचार का अभियान चलाया जाता है। एक फ्रेंच संगठन 'शेरपा' ने राफेल विमान करार में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके आधार पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव का अभियान चलाया था-'चौकीदार चोर है।' सोरोस ही 'शेरपा' का बुनियादी आर्थिक स्रोत है। कांग्रेस की ही हालिया 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी के साथ जॉर्ज के एनजीओ का वाइस प्रेजीडेंट सलिल शेट्टी भी चलता हुआ देखा गया। इसके पहले सलिल भारत में 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' का महासचिव था। भारत-विरोधी गतिविधियों के कारण सरकार ने उस संगठन को बंद कराया, लेकिन राहुल गांधी के साथ सलिल की मौजूदगी के मायने क्या समझे जाएं? बहरहाल आम चुनाव के लगभग एक साल पहले ही ये भारत-विरोधी हरकतें सामने आई हैं, जिनका सभी नागरिकों को विरोध करना चाहिए।

21 फरवरी का इतिहास

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार फरवरी 21 किसी वर्ष में दिन संख्या 45 है। भारत और विश्व इतिहास में 21 फरवरी का अपना ही एक खास महत्व है, क्योकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं हैं। आईये जानते हैं 14 फरवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ जिन्हे जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित तथ्य ऐसे होंगे जैसे : आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आजादी, नई तकनिकी का अविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस इत्यादि।

21 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएँ विश्व में ⚡

वर्ष	घटना/वारदात/वृत्तांत
1735	महान पीटर की बेटी के सम्मान में सेंट अण्णा को रूस में स्थापित किया गया।
1747	खगोल विज्ञानी जेम्स ब्रैडली ने रॉयल सोसाइटी, लंदन के लिए अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति को देने की खोज प्रस्तुत की।
1779	अंग्रेजी खोजकर्ता जेम्स कुक कीलेकेकुआ के पास मारे गए थे जब उन्होंने हवाई द्वीप के शासक प्रमुख कलानी पु यू का अपहरण करने की कोशिश की थी।
1814	वौचैप्स का युद्ध में फ्रांस के नेपोलियन I ने वॉन ब्लूचर के खिलाफ विजय प्राप्त की।
1820	वियतनाम में मिन्ह मांग का शासन शुरू हुआ।
1835	लैटरडेय संत आंदोलन के बारह के मूल कोरम के सदस्यों को तीन गवाहों द्वारा चुना गया था।
1859	ओरेगन को 33 वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया।
1876	आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एलीशग्रे ने प्रत्येक ने टेलीफोन के लिए एक पेटेंट दायर किया, जिसके बारे में एक विवाद शुरू हुआ।
1899	अमेरिकी कांग्रेस ने वोटिंग मशीन का उपयोग कर शुरू किया।
1912	पहली डीजल पनडुब्बी लंदन के पास ग्रोटन शहर में बनाई गई।
1919	वर्तमान समय के बिरोजा, बेलारूस के पास पोलिश-सोवियत वार्टूक स्थान का पहला गंभीर सशस्त्र संघर्ष।
1924	कम्प्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी ने खुद का नाम बदलकर इंटरनैशनल बिज़नेस मशीन रखा, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
1938	सिंगापुर में ब्रिटिश नौसैनिको ने ऑपरेशन शुरू किया।
1939	जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को शुरू किया गया।
1942	बिलिन नदी की लड़ाई बर्मा में शुरू हुई।
1943	द्वितीय विश्व युद्ध : जनरल हंस-जुर्गन वॉन अर्निम के पांचवें पैंजर सेना ने ट्यूनीशिया में मित्र देशों की स्थिति के खिलाफ एक ठोस हमला किया।
1945	पेरू, पराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने।

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए बजट जरूरी

प्रो. सुरेश शर्मा

हिमाचल प्रदेश की कला-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। कलाकारों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाना चाहिए'

सामान्य शब्दों में संस्कारों की ऐसी एक सुकृति जो हमारी जीवन शैली को सरल, सौम्य, सभ्य, शिष्ट तथा सुंदर बनाती है, संस्कृति कहलाती है। संस्कृति एक विशाल शब्द है जिसे परिभाषित करना इतना सरल भी नहीं है लेकिन विद्वानों द्वारा दी गई अनेकों परिभाषाओं में यह स्वीकार किया गया है कि संस्कृति का संबंध हमारे खान-पान, रीति-रिवाज, धर्म-कर्म, वेशभूषा, देव संस्कृति, पूजा पद्धति, मान्यता, विश्वास, परिधान, कला, भाषा, सभ्यता, संस्कार, व्यवहार, आचरण तथा समग्र जीवन शैली से ही है। अतः कौन सी परिभाषा सही एवं उपयुक्त है, इसका निर्णय नहीं हो सकता। अपने आप में जीवन की व्यापकता की अनगिनत परतों को समेटे यह शब्द नित्य नवीन एवं जीवंत रहेगा। लोक संगीत, लोक कला, लोक परम्परा, लोक नाट्य, लोक भाषा, लोक संस्कृति तथा लोकाचार के बिना न तो आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है, न ही कल्पना की जा सकती है। आश्चर्य है कि यह सब जीवन का अटूट अंग होते हुए हम उसका मूल्य नहीं समझते। कोई भी समाज, सभ्यता, संस्कृति तथा राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक उसकी परम्पराएं, कलाएं, संस्कृति तथा नैतिक एवं मानवीय मूल्य जीवंत नहीं हैं। दुःख इसी बात का है कि आज भौतिकवादी परिवेश में ऐसी बातों की चर्चा करना भी हास्यास्पद हो जाता है और हम बनते हैं उपहास के पात्र। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह सब होना बुद्धि की कंगाली है। आज हमने सभी क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं, परंतु सांस्कृतिक चेतनता के महत्त्व को समझते हुए हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वर्तमान में हम पाश्चात्य तथा भौतिकवाद की आंधी में उड़ कर भारतीयता की जड़ों से विमुख हो रहे हैं।

भौतिकवादी सुख का आनंद प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसमें लिप्त हो जाना सांस्कृतिक विचार की दृष्टि से चिंतन का विषय है। इसलिए सभी महान संस्कृतियों को प्रणाम करते हुए भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर विचार करना आवश्यक है। अपनी पुरातन सभ्यता या संस्कृति से जुड़े रहना कोई रूढ़िवादिता या संकीर्णता नहीं है, बल्कि अपने अतीत पर गौरवान्वित होने का विषय है। यह हमारा आधार है और जितनी नींव मजबूत होती है, भविष्य की इमारत उतनी ही विशाल, सुंदर तथा सशक्त होती है। वर्तमान में हम सांस्कृतिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व के अनेकों देश भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हम उससे मुख मोड़ रहे हैं। जीवन में सब कुछ आवश्यक है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत की कीमत पर नहीं। यह हमारे जीवन का आधार है, विरासत है तथा पूंजी है। संस्कृति का विघटन होना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन इसे सुरक्षित करने की ज़िम्मेदारी परिवारों, समाजों, सम्प्रदायों, व्यवस्थाओं तथा सरकारों की सामूहिक है। वर्तमान में सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़, सुरक्षा, बिजली, पानी, उद्योग तथा चहुंमुखी विकास की बात तो करती है, लेकिन जब सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन की बारी आती है तो बजटीय प्रावधानों में निराशा ही मिलती है। साधारणतः इस विषय को समझने वाले नीति निर्धारक इसका मूल्य नहीं समझ पाते कि इसी सांस्कृतिक धरोहर की जमीन पर हमारा अस्तित्व निर्भर करता है।

नई प्रदेश सरकार अपना पहला बजट विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने वाली है। निश्चित रूप से सरकारों की अपनी-अपनी प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता होती है। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन वादे करते हैं तथा उनकी आशाओं तथा आकांक्षाओं पर उतरने का प्रयास करते हैं, परंतु सांस्कृतिक चेतनता जगाने तथा लोक परम्पराओं, लोक कलाओं, लोक विधाओं का संरक्षण करने में कोई अधिक बजट की आवश्यकता नहीं होती। इन सभी के संरक्षण के लिए लोक कलाकारों को आर्थिक संरक्षण देना तथा लुप्त हो रही कलाओं, लोक शैलियों, लोक भाषाओं को आर्थिक सहायता देकर संजीवनी दिया जाना अति आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में कई वर्षों से एक सशक्त सांस्कृतिक नीति की मांग हो रही है ताकि इसके संरक्षण के लिए कोई नीति संहिता का निर्माण हो सके। अनेकों कलाओं तथा कलाकारों की कृतियों तथा उनके परमपरित व्यवसायों का संरक्षण किया जा सके। पुश्तैनी, परम्परागत, पीढ़ी दर पीढ़ी घरानों, परिवारों, व्यक्तियों, जातियों, समुदायों की कलाओं का संरक्षण किया जा सके। आज समाज का सामान्य, साधारण व्यक्ति भी भौतिकवाद की चपेट में आ चुका है। सरकारी संरक्षण न होने से अपना परम्परागत विरसा व्यवसाय, लोक परम्पराओं को छोड़ कर छोटा-मोटा काम-धंधा, नौकरी, दिहाड़ी-मजदूरी, खोखा, ढाबा करने पर मजबूर हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें इन लोगों को आश्रय देने की बात तो करती हैं, लेकिन यही वर्ग उपेक्षित रहता है। आज शिक्षा के साथ कौशल विकास, स्थानीय खानपान, कला, संस्कृति तथा 'वोकल फार लोकल' की बात तो की जाती है, परंतु धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। लोक कलाओं के वास्तविक वाहक तथा समाजिक रूप से अधिकृत पेशेवर लोक कलाकारों को चयनित कर उन्हें आर्थिक संरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

सरकार के नियंत्रण तथा दिशानिर्देश में चल रहे मंदिर ट्रस्टों से प्राप्त होने वाली आय की कम से कम बीस प्रतिशत राशि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए व्यय होनी चाहिए। पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटन से प्राप्त आय का भी कुछ भाग सांस्कृतिक संरक्षण पर खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि यह धनराशि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों एवं धार्मिक संस्थानों से प्राप्त होती है। सभी प्रकार की लुप्त होती कलाओं तथा कलाकारों को चिन्हित कर उनके प्रशिक्षण के लिए निरंतर कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। वृद्ध कलाकारों को प्रशिक्षण के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी कलाओं का सम्प्रेषण हो सके। कला-संस्कृति से सम्बन्धित सभी विभागों की वार्षिक एवं निश्चित कार्ययोजना होनी चाहिए। ज़िला स्तर पर भाषा अधिकारियों के साथ कला एवं संस्कृति अधिकारियों के पदों का सृजन होना चाहिए। ज़िला स्तर पर सांस्कृतिक अधिकारियों को लोक कलाओं, लोक कलाकारों, लोक वाद्यों, लोक साहित्य, लोक भाषा, लोक परम्पराओं, लोक नृत्यों, लोक वाद्यों, लोक नाट्यों, लोक परिधानों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। प्रत्येक पंचायत तथा नगर पंचायत में एक सामुदायिक पुस्तकालय होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की कला-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। लोक कलाओं के पुश्तैनी तथा परंपरित घरानेदार कलाकारों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाना चाहिए।

जस्टिस गवर्नर व अदालत की गरिमा

भाजपा और आंध्र सरकार के बीच कई बार टकराहट हो चुकी है। यदि राजनीतिक धरना-प्रदर्शन के हालात बनते हैं तो वह सिर्फ राज्यपाल के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के खिलाफ भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के कारण राज्यपाल को विवादों में घसीटा जाएगा। राजनीति में चूंकि आरोप-प्रत्यारोपों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए विवाद किसी भी हद तक जाने पर इसकी चपेट में सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बने जज भी आएंगे। राज्यपाल से सरकार और विधानसभा से होने वाली टकराहट के कई मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। जज के राज्यपाल बनने पर यदि ऐसी नौबत आती है, तो अदालतों को अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा'

भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों की तीखी आलोचना करती आई है। इस आलोचना का तात्पर्य यह नहीं है कि भाजपा भी इन्हीं दलों की तरह आचरण करने लगे और दलील यह दे कि ऐसा तो उनके शासन में भी होता रहा है, इसलिए इसमें गलत क्या है। भाजपा की केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करने के मामले में ऐसी ही दलील दे रही है। भाजपा यह कहते हुए नजीर की नियुक्ति को जायज ठहरा रही है कि ऐसा तो कांग्रेस के शासन में भी होता रहा है। भाजपा यह भूल गई कि कांग्रेस ऐसे कारनामों के कारण सत्ता से बाहर है। भाजपा अपनी सुविधा से यह नहीं कर सकती कि जिसमें उसे नुकसान नजर आए उसमें काग्रेस को कोसे और जहां छिपा हुआ एजेंडा लागू करना हो, वहां कांग्रेस का उदाहरण पेश कर दे। इस नकारात्मक उदाहरण से निश्चित तौर पर भाजपा और न्यायाधीशों की छवि पर उंगलियां उठेंगी। न्यायाधीश नजीर का गलत उदाहरण पेश करके भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सवाल यह नहीं है कि नजीर ने सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए अयोध्या और तीन तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था।

बड़ा सवाल न्यायपालिका की नैतिकता और शुचिता का है जिसे बनाए रखने की मौजूदा दौर में कम से कम किसी राजनीतिक दल से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। नजीर को राज्यपाल बनाए जाना एक तरह से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों के पुनर्वास का रास्ता देना है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के ऐसे जज जिन्होंने सरकारों के पक्ष में फैसला दिया होगा, वे सत्ताधारी दलों के कृपापात्र होंगे। जब भी सही मौका मिलेगा सरकार उनका पुनर्वास करके उन्हें अनुग्रहित कर देगी। यह परिपाटी न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि देश की न्याय व्यवस्था के भी अनुकूल नहीं है। किसी लालच या आकर्षण के बूते दिए गए फैसलों में यह पता लगाना आसान नहीं होगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। यही माना जाएगा कि सरकार का साथ देने के फैसलों के एवज में किसी प्रशासनिक या संवैधानिक पद पर नियुक्त करके न्यायाधीश को उपकृत किया गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं के दामन तो दागदार होते रहे हैं, किन्तु यह बुराई यदि न्यायपालिका तक पहुंच गई तो न्याय पर आम लोगों का विश्वास कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। सेवानिवृत्त होकर किसी पद को लेने पर न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान दिए गए फैसलों पर सवाल उठेंगे, जैसे कि जज नजीर की नियुक्ति को लेकर उठ रहे हैं। देश में पहले ही न्याय पाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। न्याय पाने के लिए होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यायपालिका जजों की कमी से जूझ रही है। जटिल न्यायिक प्रक्रिया से लोगों की हताशा बढ़ रही है। ऊपर से यदि यह प्रवृत्ति न्यायाधीशों की घर कर गई कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उनका भला कर देगी, तो न्यायिक फैसलों से आम लोगों का न्यायपालिका पर बचा हुआ विश्वास भी दरकने लगेगा।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ताजपोशी से इस बात को बल मिलता है कि केंद्र सरकार किसी न किसी रूप में न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार के राज्यपाल के पद को भरने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हो, किन्तु न्यायाधीशों को इसमें शामिल करने से न्यायपालिका और सरकार की साख पर सवाल उठना लाजिमी है। केंद्र सरकार वैसे ही जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से टकराव के मुहाने पर खड़ी है। सरकार ने कॉलेजियम के जरिए होने वाली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से इंकार कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के मसले पर सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य घोषित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि ऐसा करके सरकार न्यायपालिका में दखलअंदाजी करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के चहेतों की नियुक्ति की जाती है, वहीं न्यायविदों का कहना है कि सरकार अपने कृपापात्रों को नियुक्त कराने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को मानने से इंकार कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति कराने पर आमदा है, वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त जजों को मलाईदार पोस्ट देकर न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। राज्यपाल पद कहने को संवैधानिक होता है, किन्तु यथार्थ में राज्यपाल के राजनीतिक विवादों में घिरे रहने के कई उदाहरण मौजूद हैं। गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार में टकराव की घटनाएं होती रहती हैं।

ब्रीफ न्यूज

बाजार में 'हिंडनबर्ग इफेक्ट', उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा, निफ्टी लाल निशान पर बंद

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में जारी उठा-पटक जारी है। गुरुवार के कारोबारी सेशन में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224.16 अंकों की बढ़त के साथ 59,932.24 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 5.90 अंकों की गिरावट के साथ 17610.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 156 अंकों की मजबूती के साथ 40669 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। गुरुवार को बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 27 फीसदी की गिरावट के साथ 1565 रुपये के स्तर पर बंद हुए। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में यह 1495 रुपये तक फिसला। यह कंपनी के पिछले 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर है। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट का बड़ा कारण सिटी ग्रुप की तरफ से लिया गया फैसला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिटी ग्रुप ने अदाणी सिक्योरिटीज के मार्जिन लोन पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे पहले क्रेडिट सुईस ने अदाणी समूह के बॉन्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके बाद सिटी ग्रुप के फैसले की खबरें आईं। इन खबरों के बाद अदाणी समूह के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा और अधिकतर स्टॉक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। बजट 2023-24 में सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद आईटीसी के शेयरों में करीब 5 फीसदी की तेजी दिखी। गुरुवार को यह 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

बायजू ने करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कंपनी ने बताई छंटनी की यह बड़ी वजह

नई दिल्ली। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एडटेक यूनिकॉर्न बायजू ने करीब 1,500 कर्मचारियों की छंटनी की है। छंटनी ने मुख्य रूप से डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन कार्यक्षेत्र से कर्मचारियों को प्रभावित किया है। अक्तूबर में बायजू ने करीब 2,500 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जो उसके कार्यबल का 5 फीसदी था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बायजू के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायजू रवींद्रन ने अक्तूबर में कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि नियोजित 2,500 कर्मचारियों से आगे कोई छंटनी नहीं की जाएगी। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर केयर, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस और अन्य क्षेत्रों में कुछ कार्यों को आउटसोर्स करने की योजना बना रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, प्रबंधन मौजूदा कर्मचारियों के जाने से पहले नए भागीदारों को लाना चाहता था। छंटनी अब हुई है। उन्होंने कहा, अभी कंपनी कर्मचारियों के साथ ज्यादातर संवाद व्हाट्सएप के माध्यम से कर रही है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह बात कम लीक हो... कंपनी ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद हमें सेवरेंस पैकेज का आश्वासन दिया है। टाइगर ग्लोबल समर्थित एडटेक यूनिकॉर्न की ताजा छंटनी ऐसे समय में हुई है, जब स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार फंडिंग की कमी से जूझ रहा है। अकेले जनवरी 2023 के पहले दो हफ्तों में कम से कम 1500 स्टार्टअप कार्यबल ने नौकरी खो दीहै। पिछले एक साल में 22,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है। बायजू के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, इस बार वाइस प्रेसीडेंट और शीर्ष स्तर के प्रबंधक भी प्रभावित हुए हैं। जबकि हटाए गए कर्मचारियों में से अधिकांश या 95% जूनियर पदों पर हैं, ये सीनियर लेवल की भूमिकाओं का हिस्सा थे।

शेयर बाजार की पूंजी के लिहाज से भारत फिर पांचवें स्थान पर पहुंचा, जानें किस देश से था पिछड़ा?

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली. अदाणी समूह के शेयरों की बिकवाली के दौरान फ्रांस से कुछ समय के लिए पिछड़ने के बाद बाद भारत ने मूल्य के हिसाब से दुनिया के शीर्ष इक्विटी बाजारों में पांचवें स्थान पर फिर से कब्जा कर लिया है। ब्लूमबर्ग की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को 3.15 ट्रिलियन डॉलर था, जो फ्रांस से अधिक है। सूची में ब्रिटेन सातवें स्थान पर है। इस सूची में प्रत्येक देश में प्राथमिक लिस्टिंग वाली कंपनियों के संयुक्त मूल्य को दर्शाया जाता है।

आय वृद्धि के परिदृश्य से दक्षिण एशियाई देश के शेयरों में मजबूती आई है। जिन्होंने पिछले दो वर्षों से अधिकांश वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत के बाजार का कुल मूल्य 24 जनवरी की तुलना में अब भी लगभग 6% कम रहा। अदाणी शेयरों में बिकवाली शुरू होने से एक दिन पहले बाजार वर्तमान की तुलना में अधिक मजबूत थे। हालांकि निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए समूह की ओर से उठाए गए कदमों से इसके शेयरों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अदाणी समूह मार्केट कैप में पहले की तुलना में लगभग 120 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है।

नवंबर महीने के बाद भारतीय शेयर बाजारों से धन निकालने के बाद विदेशी निवेशक इस महीने के 9 फरवरी तक सात में से दो सत्रों के दौरान शुद्ध खरीदार रहे। यह खरीद फरवरी की शुरुआत में पूंजीगत खर्च बढ़ाने की सरकार की योजना के बाद की गई थी। जबकि केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह ब्याज दर में वृद्धि की धीमी गति का भी संकेत दिया है।

हफ्ते के पहले दिन बाजार में सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स 30 अंक चढ़ा, निफ्टी 17850 के पास

नई दिल्ली. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सपाट शुरुआत हुई है। शुरुआत में 40 अंकों की बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली हावी होती दिखी। फिलहाल सेंसेक्स 149.50 अंकों की बढ़त के साथ 60,533.20 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 31.20 अंकों की बढ़त के साथ 17825.30 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान डेल्हीवरी शेड्स के शेयरों में 5% की गिरावट जबकि अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में 2 प्रतिशत की बढ़त दिख रही है। शुरुआती कारोबार में टाटा स्टील और पावरग्रिड जैसे शेयरों में दिखी उछाल बाजार में शुरुआताी कारोबार में आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी दिख रही है। इंफोसिस के शेयरों में दो प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर सोमवार के कारोबारी सेशन के दौरान मेटल सेक्टर के शेयरों में मजबूती है। अदाणी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भी हल्की मजबूती दिख रही है। टाटा स्टील, टाइटन, पावरग्रिड और एलएंडटी के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

शीर्ष-7 शहरों में मकानों का किराया 23% बढ़ा, सबसे ज्यादा नोएडा सेक्टर-150 में हुई वृद्धि

नई दिल्ली. संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच एक हजार वर्ग फुट वाले दो बीएचके फ्लैट के किराये सभी सात शहरों में बढ़े हैं। देश के शीर्ष सात शहरों में पिछले तीन सालों में मकानों के औसत मासिक किराये में 23 फीसदी की वृद्धि हुई है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच एक हजार वर्ग फुट वाले दो बीएचके फ्लैट के किराये सभी सात शहरों में बढ़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा 23 फीसदी की बढ़त नोएडा सेक्टर 150 में हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा सेक्टर 150 में 2019 में 1,000 वर्ग फुट के 2 बीएचके मकान का किराया 15,500 रुपये था। 2022 में यह बढ़कर 19,000 रुपये हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि ज्यादा कंपनियां अब कर्मचारियों को ऑफिस बुला रही हैं, इसलिए मकानों की मांग बढ़ रही है।

2 बीएचके का किराया

शहर	2019	2022
गुरुग्राम	25,000	28,500
द्वारका	19,500	22,000
मुंबई	45,000	51,000
कोलकाता	19,000	22,000
बंगलूरू	21,000	24,000
पुणे	17,500	21,000
चेन्नई	16,000	18,000

रिपोर्ट में कहा गया है कि मकानों का किराया इस साल भी बढ़ सकता है। कर्मचारी अब घर खरीदने के बजाय कुछ समय तक किराये पर ही रहने की सोच रहे हैं। हैदराबाद के हाईटेक शहर में तीन साल में किराया 7 फीसदी बढ़कर 24,700 रुपये मासिक हो गया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में निकाले 9,600 करोड़, महंगा है भारतीय बाजार

एफपीआई ने जनवरी में कुल 28,852 करोड़ रुपये की निकासी बाजार से की थी। पिछले सात महीने में किसी एक माह में यह सर्वाधिक निकासी थी। दिसंबर में इन्होंने 11,119 करोड़ और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ने चालू माह में 10 फरवरी तक शेयर बाजार से 9,600 करोड़ रुपये निकाले हैं। भारतीय बाजार का मूल्यांकन अन्य बाजारों की तुलना में महंगा है। इसलिए विदेशी निवेशक इन पैसों को दूसरे उभरते बाजारों में लगा रहे हैं। हालांकि, डेट बाजारों में इन्होंने 2,154 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने जनवरी में कुल 28,852 करोड़ रुपये की निकासी बाजार से की थी। पिछले सात महीने में किसी एक माह में यह सर्वाधिक निकासी थी। दिसंबर में इन्होंने 11,119 करोड़ और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विश्लेषकों का मानना है कि आगे चलकर विदेशी निवेशकों का रुझान उतार-चढ़ाव का रहेगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में लगातार छठीं बार वृद्धि की है। जब तक अदाणी समूह के मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं आती है, तब तक विदेशी निवेशकों का यह रुझान बना रहेगा।

28,852 करोड़ रुपये की जनवरी में हुई थी शेयर बाजार से निकासी

विदेशी निवेशकों ने वित्तीय सेवाओं के सेगमेंट से ज्यादा निकासी की है। हालांकि, ऑटो और कलपुर्जों वाले सेगमेंट में निवेश किया है। आईटी में जनवरी में इन निवेशकों ने बिकवाली की थी। लेकिन इस महीने इसमें खरीदारी किए हैं।

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश पर कर लगाने की तैयारी

आयकर विभाग अप्रवासी निवेशकों पर कर लगाने के मकसद से गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का पता लगाने के लिए आयकर कानून के तहत संशोधित मूल्यांकन नियम जारी कर सकता है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस संशोधन की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि आयकर अधिनियम व फेमा कानून में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के एफएमवी की गणना के लिए अलग-अलग तरीके हैं। आयकर अधिनियम के नियम 11यूए को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को (फेमा) के अनुरूप बनाने के लिए हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फिर निर्धारित किया जाएगा। 11यूए अचल संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के एफएमवी के निर्धारण से जुड़ा है।

शीर्ष-7 शहरों में मकानों का किराया 23% बढ़ा, सबसे ज्यादा नोएडा सेक्टर-150 में हुई वृद्धि

नई दिल्ली. संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच एक हजार वर्ग फुट वाले दो बीएचके फ्लैट के किराये सभी सात शहरों में बढ़े हैं। देश के शीर्ष सात शहरों में पिछले तीन सालों में मकानों के औसत मासिक किराये में 23 फीसदी की वृद्धि हुई है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच एक हजार वर्ग फुट वाले दो बीएचके फ्लैट के किराये सभी सात शहरों में बढ़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा 23 फीसदी की बढ़त नोएडा सेक्टर 150 में हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा सेक्टर 150 में 2019 में 1,000 वर्ग फुट के 2 बीएचके मकान का किराया 15,500 रुपये था। 2022 में यह बढ़कर 19,000 रुपये हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि ज्यादा कंपनियां अब कर्मचारियों को ऑफिस बुला रही हैं, इसलिए मकानों की मांग बढ़ रही है।

2 बीएचके का किराया

शहर	2019	2022
गुरुग्राम	25,000	28,500
द्वारका	19,500	22,000
मुंबई	45,000	51,000
कोलकाता	19,000	22,000
बंगलूरू	21,000	24,000
पुणे	17,500	21,000
चेन्नई	16,000	18,000

रिपोर्ट में कहा गया है कि मकानों का किराया इस साल भी बढ़ सकता है। कर्मचारी अब घर खरीदने के बजाय कुछ समय तक किराये पर ही रहने की सोच रहे हैं। हैदराबाद के हाईटेक शहर में तीन साल में किराया 7 फीसदी बढ़कर 24,700 रुपये मासिक हो गया है।

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर की कीमतें

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है।

नई दिल्ली. तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।

जानें प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत

आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं।

शहर	डीजल	पेट्रोल
दिल्ली	89.62	96.72
मुंबई	94.27	106.31
कोलकाता	92.76	106.03
चेन्नई	94.24	102.63

(पेट्रोल-डीजल की कीमत रुपये प्रति लीटर में है।)

जानिए आपके शहर में कितना है दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।

बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

उतार-चढ़ाव के बीच चुनें अच्छा निवेश, योजना के जरिये तीन से ज्यादा संपत्तियों में लगाएं पैसा

नई दिल्ली। मौजूदा दौर में हम ज्याद महंगाई, उच्च ब्याज दरों, कम तरलता, अस्थिरता और भू-राजनीतिक चिंताओं के चलते एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही, शेयर बाजारों में आगे भी भारी उतार-चढ़ाव रहने का अनुमान है। ऐसे में बेहतर फायदे के लिए आपको कई संपत्तियों में निवेश करना चाहिए। इससे आपके घाटे का जोखिम कम हो सकता है। इसका गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट... आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) एस नरेन का मानना है कि किसी निवेशक के लिए सभी परिसंपत्तियों के वर्गों में निवेश करने का सबसे आसान तरीका मल्टी-एसेट फंड है। इस एक फंड में एक ही कैटेगरी के माध्यम से तीन या अधिक संपत्तियों में आप निवेश कर सकते हैं। यह फंड इक्विटी में 10-80 फीसदी, डेट में 10-35%, गोल्ड में 10-35% और रीट एवं इनविट में 0-10% निवेश करता है। विभिन्न एसेट क्लास में निवेश की ऐसी रणनीति का उद्देश्य इक्विटी में निवेश करके पूंजी बढ़ाना, डेट में निवेश करके स्थिरता और अच्छा रिटर्न अर्जित करना है। सोने में निवेश करके महंगाई से बचाव करना है।

एनएवी में 48 गुना की बढ़त

फंड की इस स्कीम ने 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि में कभी भी नकारात्मक रिटर्न नहीं दिया है। स्थापना के बाद से इसका नेट असेट वैल्यू यानी एनएवी लगभग 48 गुना बढ़ गया है। जब पोर्टफोलियो निर्माण की बात आती है, तो इक्विटी के मामले में यह स्कीम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश कर सकती है। वृद्धि या वैल्यू स्टाइल के विपरीत इसके निवेश के तरीके अलग होते हैं। इसे अक्सर कैटेगरी के अन्य फंडों द्वारा अपनाया जाता है।

इक्विटी में ज्यादा निवेश का अवसर

इस फंड में इक्विटी में निवेश इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहां दिशात्मक कॉल के आधार पर हमें आर्थिक चक्र में रखा जाता है। इसके अलावा, स्कीम समग्र पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ाने और महंगाई को पीछे छोड़ने के उद्देश्य के लिए तेल, सोना, चांदी जैसी वस्तुओं के लिए रणनीतिक निवेश का फैसला ले सकती है। स्कीम वर्तमान में इक्विटी में ज्यादा निवेश कर रही है, क्योंकि आर्थिक रिकवरी चालू है।

डीआरआई चीफ ने कहा- बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी, हर महीने जब्त होती है 1,000 करोड़ की प्रतिबंधित वस्तुएं

राजस्व खुफिया महानिदेशालय के महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने फिक्की कास्केड के सम्मेलन में कहा कि आज तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल की तस्करी के लिए जटिल तरीकों व तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

नई दिल्ली. तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस मुद्दे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीआरआई हर महीने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबंधित सामग्री जब्त करता है। राजस्व खुफिया महानिदेशालय के महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने फिक्की कास्केड के सम्मेलन में कहा कि आज तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल की तस्करी के लिए जटिल तरीकों व तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। सिंह ने कहा, जालसाजी और तस्करी के मामले में इस तरह का अवैध व्यापार एक वैश्विक जोखिम है। इसका आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक जीडीपी को दो लाख करोड़ डॉलर की चपत

विश्व कस्टम संगठन (डब्ल्यूसीओ) के निदेशक पीके दास ने कहा कि हर साल तस्करी से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दो लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। फिक्की कास्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा, हमने सम्मेलन में जागरूकता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लिया और तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का संकल्प लिया।

पीएलआई... दूरसंचार क्षेत्र को राशि मिलनी शुरू

दूरसंचार विभाग ने 2021-22 के लिए अपना लक्ष्य पूरा करने वाले निर्माताओं को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) रकम देना शुरू कर दिया है। जीएक्स टेलीकॉम ने कहा कि उसे इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग से रकम मिली है। कंपनी के पास 3.5 लाख यूनिट जीपीओएन उपकरण बनाने की क्षमता है, जिनका उपयोग ब्रॉडबैंड नेटवर्क शुरू करने के लिए किया जाता है। वैश्विक बाजार में भारत में बने टेलीकॉम उपकरणों की मांग बढ़ी है। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा, प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली योजना के तहत जीएक्स इंडिया पहली कंपनी है।

ऑयल इंडिया को 1,746 करोड़ का लाभ

सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया को दिसंबर तिमाही में 1,746 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले यह 1,245 करोड़ रुपये था। यह इसके इतिहास में अब तक का सर्वोच्च लाभ है। कंपनी ने प्रति शेयर दस रुपये लाभांश देने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से उसके फायदे पर असर दिखा है।

टाटा स्टील की 7 कंपनियों का विलय 2024 तक होगा पूरा

टाटा स्टील की सात कंपनियों का विलय 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है। इन कंपनियों में टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट, द टिनप्लेट कंपनी, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, इंडियन स्टील एवं वायर प्रोडक्ट और टाटा स्टील माइनिंग एवं एसएंडटी माइनिंग कंपनी आदि हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टीवी नागेंद्रन ने रविवार को बताया कि सितंबर, 2022 में बोर्ड ने 7 कंपनियों के विलय को मंजूरी दी थी। इससे लागत घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि, विलय को पूरा करने में नियामकीय प्रक्रियाओं की भी भूमिका होगी और इस वजह से यह अगले वित्त वर्ष में पूरा हो सकता है।

भारत में कोई भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं करता वोट, SC की अहम टिप्पणी

एनटीवी न्यूज

सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में हर्ष बाजपेयी के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। कहा गया था कि उन्होंने अपनी सही शैक्षिक योग्यता का खुलासा नहीं किया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा के हर्षवर्धन बाजपेयी के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत में कोई भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वोट नहीं देता है।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ज्यादातर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले उम्मीदवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि को नहीं देखते हैं।

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब पीठ कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हर्ष बाजपेयी के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। कहा गया था कि उन्होंने अपनी सही शैक्षिक योग्यता का खुलासा नहीं किया था। इससे पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 में सिंह की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बाजपेयी का कार्यकाल पहले ही 2022 में समाप्त हो गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था, हालांकि भ्रष्ट आचरण के आरोप प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन तथ्य यह है कि उक्त आरोप भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आते हैं, इसके अलावा भौतिक तथ्यों और बेदाग दस्तावेजों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाता है।

टाइटलर को प्रतिनिधि बनाने पर भड़की भाजपा, कहा- मोहब्बत की बात करने वाले राहुल चला रहे नफरत की दुकान

भाजपा प्रवक्ता भाटिया ने यह भी सवाल किया कि टाइटलर को एआईसीसी प्रतिनिधि नियुक्त करके कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया, '1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले नेता को एआईसीसी का निर्वाचित सदस्य बनाया गया है।

1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के आरोपी और पूर्व सांसद जगदीश टाइटलर को एआईसीसी प्रतिनिधि बनाया गया है। जिसके बाद वह अचानक चर्चा में आ गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना करते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि टाइटलर को एआईसीसी प्रतिनिधि बनाए जाने के बाद पार्टी के चरित्र का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस का चरित्र देश में विभाजन और अराजकता पैदा करने वाला है।

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की यह कार्रवाई उनके नेता राहुल गांधी की हकीकत बयां करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 'मोहब्बत की दुकान' की बात कर रहे थे, वास्तव में वह 'नफ़रत की दुकान' खोल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता भाटिया ने यह भी सवाल किया कि टाइटलर को एआईसीसी प्रतिनिधि नियुक्त करके कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया, '1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले नेता को एआईसीसी का निर्वाचित सदस्य बनाया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे नेता कांग्रेस की रीढ़ हैं। जब राहुल गांधी की 'भारत तोड़ो यात्रा' राष्ट्रीय राजधानी में पहुंची तो व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए टाइटलर भी मौजूद थे। यह दिखाता है कि राहुल गांधी और जगदीश टाइटलर दो शरीर हैं, एक आत्मा हैं।'

कांग्रेस ने AICC के सदस्यों में किया शुमार

इस साल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के लिए (AICC) ने 61 सदस्यों की लिस्ट जारी की है। इसमें जगदीश टाइटलर को भी शामिल किया गया है। यह लिस्ट दिल्ली कांग्रेस द्वारा जारी की गई है। दिल्ली कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट करके पूरी लिस्ट शेयर की है।

चुनाव प्रचार के दौरान अचानक गिरे यूडीपी उम्मीदवार, मौत; पीएम मोदी ओपी कोहली के निधन पर जताया

एनटीवी न्यूज

मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और सोहियांग विधानसभा क्षेत्र से यूडीपी के उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह का सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान अचानक गिरने से निधन हो गया। वे एक बैठक के दौरान अचानक गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत बेथानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली के निधन पर शोक व्यक्त किया। PM ने ट्वीट किया कि उन्होंने दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांसद और राज्यपाल के रूप में जन कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वे शिक्षा क्षेत्र के बारे में भी भावुक थे।

आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे थे एचडीआर

एचडीआर लिंगदोह का 20 फरवरी की शाम निधन हो गया। वह आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे थे। एचडीआर को आमतौर पर माहे के नाम से जाना जाता था। मुकुल संगमा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वे गृह मंत्री थे। उन्होंने पहली बार हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) के टिकट पर 1988 में सोहियोंग से विधायक के रूप में जीत हासिल की थी और 1998 तक विधायक बने रहे।

1998 के विधानसभा चुनावों में वह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के आरए लिंगदोह से हार गए, लेकिन 1999 में उन्होंने सोहियोंग-नोंगस्पंग निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर एमडीसी के रूप में जीत हासिल की। फिर 2003 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने यूडीपी के आरए लिंगदोह को हराकर सोहियोंग सीट पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। वह 2018 तक सोहियोंग के विधायक के रूप में बने रहे।

2018 के आम चुनावों में वह एचएसपीडीपी के समलिन मालनगियांग से 622 मतों से हार गए। लिंगदोह को 11,338 वोट मिले, जबकि मालनगियांग को 11,960 वोट मिले थे। पांच साल के इंतजार के बाद एचडीआर को सत्ता में वापसी की उम्मीद थी।

इनसाइड

समलैंगिक जोड़े की याचिका पर होगी सुनवाई, केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को ही इस मामले की सुनवाई करेगी। विक्टोरिया गौर की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर भी कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट वकील एल विक्टोरिया गौरी की मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी। कोर्ट मामले में सात फरवरी को सुनवाई करेगी।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला वकील को पदोन्नत करने का प्रस्ताव कथित तौर पर तब विवादास्पद हो गया, जब उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कथित संबद्धता के बारे में खबरें सामने आईं। न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित वकील के मुस्लिम और ईसाइयों के बारे में कुछ बयान सामने आए हैं।

धर्मांतरणः राज्य कानूनों से संबंधित याचिकाओं पर 17 मार्च को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह जबरन धर्मांतरण के दो अलग-अलग मुद्दों और अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण होने वाले धर्मांतरण पर राज्य के विभिन्न कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया था कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उनकी याचिका उन याचिकाओं के बैच से अलग थी, जो धार्म परिवर्तन पर विभिन्न राज्य कानूनों की वैधता को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने बेंच से कहा कि मैं न तो राज्य के कानूनों का समर्थन कर रहा हूं और न ही उनका विरोध कर रहा हूं। मेरी याचिका जबरन धर्मांतरण के अलग-अलग मुद्दे से संबंधित है। उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका पर अलग से सुनवाई की मांग की।

पीएम मोदी ने की 'ऑपरेशन दोस्त' की तारीफ, भूकंप प्रभावित तुर्किये से लौटे बचाव दल के जांबाजों से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के लोगों से बात की। इन लोगों ने तुर्किये और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। भारत की ओर से भेजे गए बचाव दल ने भूकंप प्रभावित देशों में कई जानें बचाईं। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ऑपरेशन दोस्त की तारीफ की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हों, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वॉड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में राष्ट्रों के साथ खड़े होने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। हमेशा दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा के लिए भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है।

विश्व को मानते हैं एक परिवार

उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है। इसलिए तुर्किये हो या फिर सीरिया पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का प्रदर्शन किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखता है। उन्होंने कहा कि तुर्किये में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी तत्परता और तैयारी को दिखाता है। आपका प्रशिक्षण आपकी कुशलता को दिखाता है। हमारी संस्कृति ने हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम' की सीख दी है। इसलिए तुर्किए हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का प्रदर्शन किया है।हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं।

तिरंगा लोगों को देता है आश्वासन

उन्होंने कहा कि जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिसिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं, वहां लोगों को एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं, तो हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखी।

सुषमा स्वराज के सहारे महिला मतदाताओं में पैठ बढ़ाएगी BJP, शुरू होगा विशेष कमल मित्र अभियान

एनटीवी संवाददाता

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस बार अपनी दिग्गज महिला नेता सुषमा स्वराज के नाम का भी खूब इस्तेमाल करेगी। पार्टी उनके नाम से एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत भी कर सकती है। इस योजना में उन महिलाओं को पुरस्कृत किया जा सकता है, जो देश-समाज के किसी क्षेत्र में विशेष योगदान दे चुकी होंगी...

लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने के लिए भाजपा महिलाओं में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए विशेष 'कमल मित्र' योजना की शुरुआत करेगी। महिला दिवस पर इस योजना की शुरुआत कर वह महिला मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का काम करेगी। केंद्र-भाजपा शासित राज्यों की महिला कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं से मिलकर भाजपा की महिला कार्यकर्ता उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी। यह पूरा अभियान भाजपा की महिला मोर्चा शाखा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस बार अपनी दिग्गज महिला नेता सुषमा स्वराज के नाम का भी खूब इस्तेमाल करेगी। पार्टी उनके नाम से एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत भी कर सकती है। इस योजना में उन महिलाओं को पुरस्कृत किया जा सकता है, जो देश-समाज के किसी क्षेत्र में विशेष योगदान दे चुकी होंगी। इसमें राजनीति, कला, संस्कृति, खेल और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के नामों पर विचार किया जा सकता है।

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता के पीछे महिला मतदाताओं का बड़ा योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि केंद्र की महिला केंद्रित योजनाओं के कारण पीएम मोदी की लोकप्रियता उनके बीच खूब बढ़ी। बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने जाति-वर्ग और धर्म से परे हटकर भाजपा का समर्थन किया और पार्टी अपने बल पर दोबारा सत्ता में आने में कामयाब हुई।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसका मानना है कि महिला मतदाताओं के विशेष समर्थन के बिना उसका यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि महिलाओं में समर्थन बढ़ाने के लिए पार्टी विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार के बजट में महिला उन्मुखी योजनाओं की शुरुआत के बाद अब राजनीतिक-सामाजिक माध्यमों के सहारे इस पैठ को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है।

नीति आयोग के सीईओ बने सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर होंगे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक

एनटीवी संवाददाता

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। वह परमेश्वरन अय्यर की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया गया है।

कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए की गई है। नीति आयोग के सीईओ के तौर पर काम कर रहे परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के तौर पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है।

विपक्ष के 12 सांसदों के खिलाफ संसदीय समिति करेगी जांच, सभापति के वेल में पहुंचकर की थी नारेबाजी

राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक, नौ सांसद कांग्रेस के और तीन आम आदमी पार्टी के हैं। इन पर सदन के आसन के बीच में बार-बार घुसने, नारेबाजी करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप है।

संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति के वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने पर 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति से कांग्रेस और आप के 12 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच करने का निर्देश दिया है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक, नौ सांसद कांग्रेस के और तीन आम आदमी पार्टी के हैं। इन पर सदन के आसन के बीच में बार-बार घुसने, नारेबाजी करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप है।

इन सदस्यों पर के खिलाफ होगी जांच

जानकारी के मुताबिक, जिन सांसदों के खिलाफ संसदीय समिति को जांच सौंपी गई है, उनमें कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल, नारनभाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमंथैया, फूलो देवी नेताम, जेबी माथेर हिशाम और रंजीत रंजन व आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक शामिल हैं।

अदाणी मामले पर हुआ था हंगामा

बता दें, राज्यसभा और लोकसभा में अदाणी मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष के सांसद लगातार सरकार से गौतम अदाणी मामले में संयुक्त संसदीय कमेटी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर बार-बार संसदीय कार्यवाही बाधित हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा।